महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

16 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

वर्ष : 16 अंक : 327 | उज्जैन, शनिवार 09 मई 2026 | पृष्ठ-8 मूल्य-1 रुपए

सुविचार

कितनी खूबसूरती से ईश्वर आपकी जिन्दगी मे हर एक दिन जोड़ता है इसलिये नहीं कि आपको उसकी जरूरत है शायद इसलिये कि किसी और को, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है..

सांस्कृतिक धरोहर भावी पीढ़ियों को समृद्ध अतीत से जोड़ने का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार से सशक्त हो रहा सांस्कृतिक वैभव

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरें भावी पीढ़ियों को समृद्ध अतीत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास, ज्ञान, कला और सभ्यता की जीवंत प्रतीक हैं।इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन समय की आवश्यकता है, जिससे भावी पीढ़ियाँ भी अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अनुभव कर सकें। राज्य सरकार ÷विरासत भी-विकास भी÷ के संकल्प को साकार करते हुए सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है।प्रदेश में प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य निरंतर किया जा रहा है।इन प्रयासों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण देश में विशिष्ट पहचान रखता है। संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा प्रदेश में बिखरे मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक पद्धति से मूल स्वरूप में पुनर्स्थापन किया जा रहा है। 'पुनर्संरचना' एवं 'एनास्टाइलोसिस' जैसी तकनीकों के माध्यम से धरोहरों की मौलिकता और ऐतिहासिकता को संरक्षित किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनर्जीवन का महत्वपूर्ण प्रयास है।

देवबड़ला और आशापुरी बने पुरातात्विक पुनरुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण- सीहोर जिले का देवबड़ला और रायसेन जिले का आशापुरी क्षेत्र पुरातात्विक पुनरुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरकर सामने आया है। इन स्थानों की विशेषता यह है कि यहाँ मंदिरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, किंतु उत्खनन के दौरान प्राप्त बिखरे अवशेषों एवं खंडित प्रतिमाओं को वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित कर पुनर्स्थापित किया गया है।

देवबड़ला में परमारकालीन मंदिरों का किया जा रहा है पुनर्स्थापन- घने जंगलों के मध्य स्थित सीहोर जिले के देवबड़ला में 11वीं शताब्दी के परमारकालीन मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण कराया गया है। यहाँ 'भूमिज शैली' में निर्मित मंदिरों की 'पंच-रथ' योजना तत्कालीन उन्नत स्थापत्य कला का नमूना है। मंदिर क्रमांक-1 एवं 2 के पुनर्संरचना कार्य में मूल पत्थरों का उपयोग कर उनकी प्राचीनता को सुरक्षित रखा गया है। द्वार-शाखाओं पर उकेरी गई गंगा-यमुना की प्रतिमाएँ तथा सूक्ष्म नक्काशी इस स्थल को विशेष बनाती हैं।

आशापुरी में किया जा रहा है प्रतिहारकालीन मंदिरों का संरक्षण - रायसेन जिले का आशापुरी क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन मंदिर क्रमांक-17 का पुनरुद्धार किया गया है। मंदिर के वर्गाकार गर्भगृह एवं मुखमंडप को अत्यंत सावधानीपूर्वक पुनर्स्थापित किया गया है। स्थल से प्राप्त शिव-नटेश, लक्ष्मी-नारायण तथा गजासुर संहारक शिव की प्रतिमाएँ प्रदेश की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

सम्पूर्ण प्रदेश में हो रहे हैं मंदिर संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य- प्रदेश में धरोहर संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्य व्यापक स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिद्धेश्वर एवं अन्य मंदिर परिसरों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जा रहा है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किया गया है। वहीं रायसेन जिले के धवला क्षेत्र में मंदिरों की संरचनात्मक सुरक्षा एवं विशेष सफाई कार्य संपादित किए गए हैं। इन सभी स्थलों पर 'एनास्टाइलोसिस' तकनीक के माध्यम से मूल पत्थरों द्वारा पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिकता एवं मौलिक स्वरूप सुरक्षित बना रहे।

इन समेकित प्रयासों से प्रदेश न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि उन्हें नई पहचान भी प्रदान कर रहा है। प्राचीन विरासत को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने की यह पहल प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। गौरवशाली अतीत और आधुनिक तकनीक के समन्वय से संचालित यह अभियान प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और विरासत के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दे रहा है।

न्यूज ब्रीफ

पुलिस सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़कर प्रचार हासिल करने में लगी है, पंजाब में नशे के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नई दिल्ली/ जीएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने नशे के कारोबार में लगे छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर राज्य पुलिस द्वारा वाहवाही लूटने पर फटकार लगाते हुए कहा कि वे पब्लिसिटी के लिए छोटे मोटे अपराधियों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन बड़े तस्करों को आजाद घूमने देते हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े मगरमच्छों या रसूखदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये भी कहा कि लुधियाना इस तरह के कारोबार का केंद्र है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे होने वाला नुकसान चिंताजनक है और राज्य सरकार को इससे निपटने के तरीके में बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस समस्या से निबटने के लिए राज्य और केंद्र के मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। ये टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने विशेष कानूनों जैसे एनडीपीएस और यूएपीए के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कीं। इस परकोर्ट स्वत÷ संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क पर चिंता जताई। पीठ की अगुवाई कर रहे सीजेआइ सूयर्कांत ने सुनवाई के दौरान एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक महिला ने नशे की लत के कारण अपने पांचों बेटों को खो दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जरा देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। एक मां रो रही है। उसने नशे की वजह से अपना पांचवां बेटा भी खो दिया। उसने नशे की लत के कारण अपने सभी बच्चों को खो दिया। पुलिस को इस मामले में और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि नशे का खतरा अब उस हद तक पहुंच गया है, जहां केंद्र सरकार के दखल की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब वह दखल दे तो ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही है। पीठ ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के मिल कर काम करने पर जोर देते हुए कहा कि साझा लक्ष्य नशीले पदार्थों पर रोक लगाना होना चाहिए।

बिहार की लीची पर स्टिंग बग का खतरा, कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने उतारी विशेषज्ञों की टीम

नई दिल्ली/ जीएनएस। लीची पर स्टिंग बग कीटाणु के हमले की शिकायतें आने के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। विशेष कार्यबल (टास्क फोर्स) गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की टीम उतार दी गई है, जो लीची किसानों के नुकसान का आकलन करेगी और एक सप्ताह के भीतर समाधान की तलाश कर रिपोर्ट देगी। स्टिंग बग एक तरह का कीट है, जिसके हमले से लीची की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फल सिकुड़ने लगते हैं, समय से पहले गिर जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। बिहार प्रमुख लीची उत्पादक राज्य है, जहां मुजफ्फरपुर की लीची को अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लखनऊ में सात मई को आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों ने स्टिंग बग के कारण लीची को हो रहे नुकसान के बारे में बताया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेषज्ञ कार्यबल के गठन का निर्देश दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गठित टास्क फोर्स प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसल क्षति का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। टीम नियंत्रण उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीति भी सुझाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रकोप से बचाव की स्थायी व्यवस्था विकसित की जा सके। किसानों को तकनीकी सलाह देने, विस्तार गतिविधियों को तेज करने और राज्य व केंद्र स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप सुझाने की जिम्मेदारी भी इसी कार्यबल को सौंपी गई है।

गोवा सरकार का बड़ा पर्यावरणीय फैसला, वाघेरी पहाड़ी और साओ-जोर्ज द्वीप बने नो डेवलपमेंट जोन

नई दिल्ली/ जीएनएस। गोवा सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाघेरी पहाड़ी और साओ-जोर्ज द्वीप को नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) या विकास निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है।

इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना है। महाराष्ट्र-गोवा सीमा के पास स्थित वाघेरी पहाड़ी की ऊंचाई 780 मीटर है। यह गोवा के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। नगर एवं ग्रामीण योजना मंत्री विश्वजीत राणे ने गुरुवार को बताया कि पश्चिमी घाट में स्थित इस पहाड़ी को एनडीजेड घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य वन विभाग द्वारा गठित एक समिति ने पाया कि इस पहाड़ी पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए हरित आवरण या ग्रीन कवर को हटाया जा रहा है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।अधिसूचना के अनुसार, सत्तारी तालुका में स्थित वाघेरी पहाड़ी 65.31 लाख वर्ग मीटर में फैली है। इस पर प्राकृतिक आवरण है और इसकी ढलान सिंचाई कमांड क्षेत्र से मिलती है। सरकार ने मोरमुगाओ में स्थित 6.63 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र वाले साओ-जार्ज द्वीप को भी इसके विरासत मूल्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एनडीजेड घोषित किया है। जनता अधिसूचना की तारीख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य नगर योजनाकार को अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकती है।

नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने दक्षिण गोवा के माजोर्डा गांव में रेत के टीलों और सिंचाई कमांड क्षेत्र की रक्षा के लिए 2.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को विकास निषेध क्षेत्र घोषित करने को भी मंजूरी दे दी है। गोंसुआ गांव में 1.95 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में भी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

लू और बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा करेंगे अमित शाह, रविवार को होगी हाई लेवल बैठक

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लू और बाढ़ की संभावित स्थितियों से निपटने के लिए देश की तैयारियों की रविवार को व्यापक समीक्षा करेंगे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, अमित शाह केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर-एजेंसी समन्वय की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ताकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं होने पाए और संपत्ति को न्यूनतम क्षति पहुंचे।

बैठक के दौरान गृह मंत्री उन्नत तकनीक और रियल टाइम डाटा एकीकरण के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की स्थिति का आकलन करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

22 साल से जेल में बंद हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर जताई चिंता

नई दिल्ली/ जीएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा पारित एक परेशान करने वाले आदेश का संज्ञान लेते हुए हत्या के एक दोषी को जमानत दे दी। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस दृष्टिकोण पर गंभीर चिंता जताई, जिसने देरी के आधार पर उसकी अपील खारिज कर दी थी।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को मामले पर व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और दोषी को उसकी अपील पर मेरिट के आधार पर बहस करने का अवसर देने के लिए देरी को माफ कर देना चाहिए था। शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि दोषी को एक बार भी पैरोल या फर्लो पर रिहा नहीं किया गया और कहा कि मामले को हाई कोर्ट में वापस भेजना और आपराधिक अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करना व्यर्थ होगा।

धार्मिक धागे और आस्था से जुड़ी चीजें पहनने की अनुमति, एनटीए ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली/ जीएनएस। कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी आस्था से जुड़ी चीजें या वस्तुएं पहनने की अनुमति होगी, बशर्ते वे तलाशी के लिए केंद्र पर काफी पहले पहुंच जाएं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों के लिए जारी एडवाइजरी में यह जानकारी दी गई है। एनटीए ने कहा, इस बात पर जोर दिया जाता है कि कलावा जैसे धार्मिक धागे पहनने की अनुमति है।

एडवाइजरी में क्या-क्या है- एडवाइजरी में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड और किन चीजों को ले जाने की अनुमति है, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। सीयूईटी-यूजी 2026 भारत में 11 मई से 31 मई तक और देश के बाहर 15 शहरों में आयोजित किया जाएगा। एडवाइजरी के अनुसार, परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शी पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति होगी।

भारत का अलिखित फैसला: होर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए नहीं होगा नकदी भुगतान

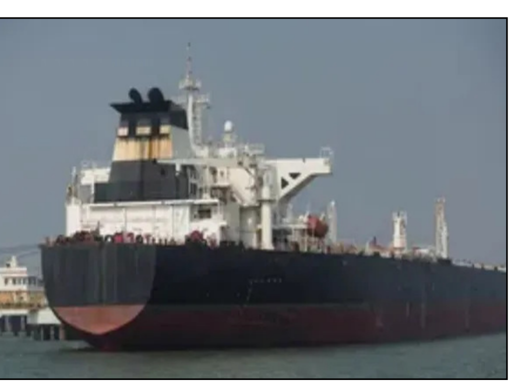

नई दिल्ली/ जीएनएस। पश्चिम एशिया में 1 मार्च 2026 को शुरू हुए संघर्ष के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर भारत एक सख्त और अलिखित नीतिगत फैसला पर कायम है, वह यह है कि कोई भी भारतीय कंपनी या जहाज मालिक ईरान को किसी भी रूप में वित्तीय भुगतान करके बाहर नहीं निकलेगा। अभी भी 14 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं।

संघर्ष शुरू होने पर कई जहाजों को ईरानी नौसेना ने रोक लिया था या हमले का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राजनयिक बातचीत और अंतरराष्ट्रीय दबाव के जरिए 11 जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन बिना किसी आर्थिक समझौते के।

जानकारों का कहना है कि गैर-खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी के कारण यह फैसला भारत के लिए अपेक्षाकृत आसान हो गया है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह भारत की स्पष्ट नीति है कि जहाजों को होर्मुज से बाहर निकालने के लिए किसी भी पक्ष को किसी तरह का वित्तीय भुगतान नहीं किया जाएगा।

उक्त अधिकारी के मुताबिक, ÷हमारी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता पर जोखिम है लेकिन किसी भी देश को टोल टैक्स या रिहाई शुल्क के रूप में पैसे देने से गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। जबकि कई मीडिया रिपो?र्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अन्य देशों के जहाजों को ईरान सरकार ने टोल टैक्स या स्थानीय बैंक के जरिए भुगतान लेकर ही गुजरने की अनुमति दी। भारत का मानना है कि ऐसा भुगतान न सिर्फ सुरक्षा जोखिम बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में समुद्री मार्गों पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा।अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज जल मार्ग के मुहाने पर नाकेबंदी कर रहे अमेरिकी पक्ष को भारतीय जहाजों के आवागमन के लिए राजी करना मुश्किल नहीं है। असली समस्या होर्मुज जल मार्ग के अंदर विभिन्न बंदरगाहों पर अटके जहाजों को बाहर लाने की है।

जैसलमेर में बाइक पर रखे AC गैस सिलेंडर में विस्फोट, उछलकर दूर गिरा युवक; गंभीर रूप से घायल

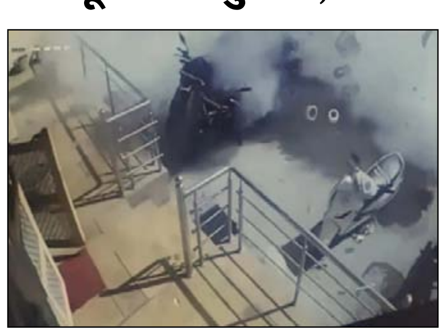

नई दिल्ली/ जीएनएस। जैसलमेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में शुक्रवार सुबह भीषण हादसा हो गया। यहां करीब 10÷30 बजे एक बाइक पर रखे एयर कंडीशनर गैस भरे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में बाइक पर सवार युवक जोरदार धमाके के साथ हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा।

बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में विस्फोट- हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सिलेंडर कई हिस्सों में टूट गया और आसपास की इमारतों तक आवाज गूंज गई। यह पूरी घटना होटल किशनगढ़ के सामने हुई। जहां गफूर भट्टा निवासी चंद्रप्रकाश (25) पुत्र नखताराम माली अपने साथी सवाई राम के साथ काम पर निकला था। दोनों जोधपुर से रिफिल कराए गए आर-32 गैस सिलेंडर लेकर बस से जैसलमेर पहुंचे थे। बस से सिलेंडर लेने के बाद वे होटल के पास सामान उठाने के लिए रुके।

सवाई राम बाइक से उतरकर अंदर गया ही था कि बाइक के पिछले हिस्से पर रखे कार्टन में बंद सिलेंडर फट गया। चंद्रप्रकाश बाइक पर मौजूद था, धमाके के झटके से बेहोश होकर सड़क पर जा गिरा।

पुलिस कर रही विस्फोट के कारणों की जांच- मौके पर मौजूद लोगो के अनुसार ब्लास्ट की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले। होटल मालिक पुरुषोत्तम ने तुरंत घायल युवक को अपनी गाड़ी से जवाहिर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रप्रकाश को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके कमर में चोट आई है और अंदरूनी चोटें गंभीर हैं।

नगर परिषदों में चल रहे शहरी विकास कार्यों की कलेक्टर शिवम वर्मा ने की विस्तृत समीक्षा

स्वच्छता सर्वेक्षण, पीएम आवास, अमृत 2.0 एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज इंदौर जिले की सभी नगर परिषदों में संचालित शहरी विकास एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं नागरिक सहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आवासीय पट्टा वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने पात्र हितग्राहियों को पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अमृत 2.0 योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी निर्माण एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों को गुणवत्ता एवं समय-सीमा के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी अधिकारी तथा संयुक्त कलेक्टर श्री ओमनारायण बड़कुल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों एवं माह मई 2026 में जारी होने वाली ग्रेडिंग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए तथा अनावश्यक लंबित प्रकरणों को तत्काल समाप्त किया जाए। उन्होंने भूमि आवंटन से संबंधित लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के त्वरित परीक्षण एवं निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही निकायों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में नगरीय विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई तथा सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज ग्राम कम्पेल एवं पिवडाय में शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर संबंधित कॉलेज प्रशासन को कब्जा दिलाया गया। यह कार्रवाई एसडीएम श्रीमती प्रियंका चौरसिया के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा की गई। एसडीएम श्रीमती चौरसिया ने बताया कि संबंधित भूमि शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा फसल बुवाई कर अवैध कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन द्वारा आज मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का विधिवत कब्जा शासकीय कॉलेज के प्राचार्य श्री कुम्भन खंडेलवाल को सौंप दिया गया। जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

एमआर-4 रोड चौड़ीकरण में बाधक दो फैक्ट्रियों के हिस्से हटाए गए

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम इंदौर द्वारा एमआर-4 मास्टर प्लान रोड चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत बाधक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को निगम ने डीआईसी भूमि पर निर्मित दो फैक्ट्रियों के बाधक हिस्सों को हटाया। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई के तहत दिवाकर कॉपी हाउस एवं विद्या इंटरप्राइजेज के उन हिस्सों को हटाया गया, जो 30 मीटर चौड़ी एमआर-4 मास्टर प्लान रोड निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। निगम द्वारा केवल बाधक हिस्से को हटाते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई। नगर निगम की योजना शाखा द्वारा एमआर-4 मास्टर प्लान रोड का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत मार्ग में आने वाले अवैध एवं बाधक निर्माणों को चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि सड़क निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। निगम अधिकारियों के अनुसार दोनों प्रकरणों में पूर्व में माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त था, लेकिन दिसंबर 2025 में संबंधित मामलों का निराकरण हो चुका है। संबंधित भूमि डीआईसी की स्वामित्व भूमि होने के कारण डीआईसी द्वारा नगर निगम को बाधक निर्माण हटाने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों फैक्ट्रियों के बाधक हिस्सों को हटाया। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी आशीष राठौर, भवन निरीक्षक आराधना शुक्ला, योजना शाखा से देवेंद्र तंवर सहित रिमूवल विभाग की टीम और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

वार्ड 80 में आयुक्त ने किया स्वच्छता संवाद, नागरिकों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शुक्रवार को झोन क्रमांक-21 के वार्ड क्रमांक 80 में नागरिकों के साथ स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बड़वे, अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने धनवंतरी नगर एवं प्रगति नगर क्षेत्र के रहवासियों और बच्चों से स्वच्छता को लेकर संवाद किया। उन्होंने बच्चों को दैनिक जीवन में स्वच्छ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी।

आयुक्त क्षितिज सिंघल ने उपस्थित नागरिकों को 6 प्रकार के कचरा सेग्रीगेशन एवं होम कंपोस्टिंग के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कचरे का पृथक्करण स्वच्छ शहर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाए रखने का संकल्प दिलाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में आज कलेक्टर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री पवार नवजीवन विजय द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा प्रशासन में पदस्थ सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई, नमूना संग्रहण, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति तथा प्रवर्तन संबंधी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर श्री पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी बैठक में यह प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाए कि अब तक कितने प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा कितने प्रकरण लंबित हैं।

बैठक में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अंतर्गत लगाए गए अर्थदंड की वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयीन प्रकरणों की पेशियों में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण हो सके। बैठक में आगामी समय में विभिन्न खाद्य श्रेणियों में विशेष सैंपलिंग एवं जांच अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। इनमें डेयरी उत्पाद, फैट्स एंड ऑयल्स, मसाले, सीरियल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, स्वीट्स, नट्स, प्रोटीन बार, आइसक्रीम, कुल्फी, आइस एवं जूस सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

अपर कलेक्टर श्री पवार ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण, नमूना कार्रवाई एवं प्रवर्तन कार्य सतत रूप से जारी रखे जाएं, जिससे आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

महिलाओं और बालिकाओं की साइबर सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस ने आयोजित की विशेष जागरूकता कार्यशाला

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहने और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से "Stay Safe Online - Be Aware Be Secure for Women and Girls" विषय पर एक दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, साइबर अपराधों से बचाव और कानूनी प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त राजेश त्रिपाठी, अमन सिंह राठौड़, सुनील मेहता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेन्द्र सिंह, डॉ. सीमा अलावा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रेनैसां यूनिवर्सिटी इंदौर के डायरेक्टर डॉ. दिव्यादित्य कोठारी, आईपीएस एकेडमी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की प्राचार्य मनीता सक्सेना, छात्र-छात्राएं, सामाजिक संस्था 'आस' के सदस्य और ऊर्जा डेस्क की महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुईं।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह ने स्वागत उद्बोधन के साथ किया। उन्होंने डिजिटल अनुशासन और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। फर्जी पहचान बनाकर भावनात्मक शोषण, निजी फोटो और वीडियो की मांग, साइबर ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। इसके कारण युवाओं में तनाव, अवसाद और अकेलेपन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सजग और सतर्क रहने का संदेश देते हुए कहा कि आत्मनियंत्रण, सावधानी और विवेकपूर्ण निर्णय ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन को देना चाहिए।

अतिथि वक्ता डॉ. दिव्यादित्य कोठारी ने सोशल मीडिया उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, नए साइबर कानूनों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध का शिकार होने से पहले स्वयं को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है।

जिला प्रशासन और आरटीओ की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई

अभियान चलाकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री बसों की गई सघन जांच

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में आज जिला प्रशासन और आरटीओ की संयुक्त टीम ने मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस मुहिम के तहत आज अनेक यात्री बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान अ?नियमितताएं और लापरवाही पाये जाने पर 7 बसों की फिटनेस ?निरस्त किए गए। पांच बसें जप्त की गई और पांच लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई एसडीएम श्री घनश्याम धनगर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और आरटीओ के संयुक्त टीम ने की। मुहिम में बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच की गई। इंदौर शहर में लोक परिवहन वाहनों, बसों, स्कूल वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों के साथ ही, विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज के वाहनों की सघन जाँच की जा रही है।

इसी कड़ी में आज इंदौर आरटीओ और जिला प्रशासन ने तीन इमली चौराहा, रिंगरोड पर लोक परिवहन वाहनों खासकर स्टेज कैरिज बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच की गई। कई बसो में फायर सेफ्टी उपकरण ख़राब या मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, इमरजेंसी एग्जिट बंद पाया गया, मेडिकल किट भी नहीं पाया गया। बसों में विभिन्न कमियां पाए जाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई। इस दौरान 5 बस जब्त की गई, 7 बसों के फिटनेस निरस्त किए गए और 5 लाख रुपये से अधिक बकाया टैक्स वसूल किया गया।

इस संयुक्त कार्यवाही में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम श्री घनश्याम धनगर, आरटीओ श्री प्रदीप शर्मा, एआरटीओ श्री राजेश गुप्ता एवं उड़नदस्ता टीम उपस्थित रही। साथ ही बसों के चालक-परिचालकों को भी समझाइश दी गई कि वे बसों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न करें। जिस प्रकार फ्लाइट में यात्रियों को आपातकाल स्थिति में क्या करें ,क्या न करें की जानकारी दी जाती है उसी प्रकार बसों में भी सवारियों को जानकारी दी जाए कि कहाँ इमरजेंसी एग्जिट है, कहाँ पर कांच तोड़ने का हैमर रखा है ।

स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के तहत आयुक्त ने वार्ड 80 का किया निरीक्षण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 80 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण में अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, झोनल अधिकारी हेमंत मिश्रा, सीएसआई विजय यादव, उपयंत्री अमित डोगरे, उपयंत्री नवीन बुंदेला, टीम बेसिक्स के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण के निर्धारित मानकों के अनुसार क्षेत्र में स्थित गार्डन, वाटर बॉडी, रहवासी क्षेत्र, बैक लाइन, मिक्स एरिया, कमर्शियल एरिया, ट्रांसपोर्ट हब, आदर्श बैक लाइन एवं यूरिनल सहित विभिन्न स्थानों का अवलोकन किया। उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने, नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सुधार कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

इंदौर की विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में बढ़ावा देकर मेडिकल टूरिज्म एवं वैलनेस हब की दिशा में आगे बढ़ेंगे - संभागायुक्त

जो कुछ अन्य शहर नहीं दे पा रहें है उन सुविधाएं और व्यवस्थाएं पर भी फोकस किया जाएगा

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पांच विशेष रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने की योजना है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए शुक्रवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेडिकल विशेषज्ञता रखने वाले तथा अलग-अलग क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी से इस सम्बंध में सुझाव लिए गए। ताकि इस प्रस्तावित योजना को क्वालिटी ऑफ केयर एंड क्रेडिबिलिटी के साथ स्थापित किया जा सकें। बैठक के पश्चात संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि शासन को प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने से पहले इसके दीर्घ और लघु रूप में ठोस तैयारी की जाए। बैठक में एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री हिमांशु प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म के चेयरमैन श्री हेमेन्द्र सिंह चौहान, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. डी.के. शर्मा सहित विभिन्न अस्पतालों के प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

भारत मेडिकल क्षेत्र में ग्लोबली वैलनेस डेस्टिनेशन बनता जा रहा है- बैठक के पश्चात संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि भारत मेडिकल क्षेत्र में ग्लोबली वैलनेस डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इसके लिए शासन की इस योजना को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए जो व्यवस्थाएं या सुविधाएं अन्य शहर नही दे पा रहे है, उससे कुछ अलग देने के लिए हमें फोकस होना होगा। हमारे सबसे सकारात्मक पहलुओं के साथ ही इसमें कुछ और विशेषताएं शामिल करना होगी। बैठक में वर्तमान में संचालित अस्पतालों के विशेषज्ञता वाले पैकेजेस पर चर्चा की गई। वही अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने के पूर्व आवश्यक तैयारियों के सम्बंध में अपने सुझावों के साथ आवश्यकताएं भी बताई। योजना के प्रथम चरण में अस्पतालों द्वारा किये जा रहे उपचारों और उनके पैकेज की सूची ली जाएगी, जिसके आधार पर अलग स्टेकहोल्डर्स इस दिशा में आगे बढ़ सकें। साथ ही एक पोर्टल बनाकर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इनके लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस पोर्टेबलिटी पर भी आवश्यक रूप से काम किया जाएगा। हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में भी सुझाव आये है। इसमें होम्योपैथी के साथ ही आयुर्वेद का भी कॉम्बो सेटअप करने की दिशा में काम किया जायेगा।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश में विशेष रीजनल मेडिकल हब बनाने की दिशा में कार्य किया जाना है। इस दृष्टि से प्रदेश में रीजनल मेडिकल हब के लिए उज्जैन-इंदौर कॉरिडोर बेहतर जगह है। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक ओर जहाँ उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है तो दूसरी तरफ ओंकारेश्वर में पवित्र ज्योतिर्लिंग है। दोनों ही ज्योतिर्लिंग पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश से दर्शनार्थी आते है। इंदौर में रीजनल मेडिकल हब के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हवाई सेवाएं और रेलवे की भी बेहतर कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्वास्थ्य की आधुनिक और उन्नत सेवाएं है, यहाँ बड़े-बड़े ग्रुप के हॉस्पिटल है। एयर एम्बुलेंस की बेहतर सुविधा है। इंदौर में बड़े-बड़े होटल और आसपास पर्यटक केन्द्र है। उन्होंने कहा कि भारत मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स और वेलनेस इंडेक्स में अच्छी स्थिति में है। विशेष रीजनल हब बनने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी।

चाय चौकी कैफे फायरिंग मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल जब्त

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। स्कीम नंबर-78 स्थित चाय चौकी कैफे में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले मामले में पुलिस थाना लसूडिया ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को फरियादी आर्यन पिता राजेन्द्र पटेल निवासी मां शारदा नगर ने थाना लसूडिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका अपने दोस्त ऋषभ सिंह राजपूत से चाय चौकी कैफे में विवाद हो गया था। फरियादी ने राजीनामा करने के लिए ऋषभ को कैफे पर बुलाया था, जहां विवाद बढ़ने पर ऋषभ ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कैफे में रखी कुर्सियों एवं स्टूल से हमला कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ऋषभ अपनी एक्टिवा से पिस्टल निकालकर लाया और फरियादी पर जान से मारने की नीयत से दो से तीन फायर किए। हालांकि गोली नहीं लगी। इसके बाद आरोपी ने पिस्टल की बट से फरियादी के सिर पर हमला किया, जिससे कैफे में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। इसी दौरान आरोपी का साथी हेनी उर्फ निखिल गोस्वामी पिस्टल लेकर मौके से फरार हो गया था।

मामले में थाना लसूडिया पुलिस ने अपराध क्रमांक 563/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तत्काल मुख्य आरोपी ऋषभ सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल उसका साथी हेनी उर्फ निखिल गोस्वामी लेकर फरार हो गया है।

इसके बाद पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 7 मई 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हेनी उर्फ निखिल निरंजनपुर स्थित पिंक सिटी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी।

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय किलाभवन इंदौर में अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के संरक्षण एवं योजना प्रभारी डॉ. शीतल झा के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें उद्योगों एवं संस्थानों में उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में छात्राओं को योजना की रूपरेखा, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, प्रोफ़ाइल निर्माण एवं इंटर्नशिप आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

योजना प्रभारी डॉ. शीतल झा ने बताया कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक अनुभव एवं कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता एवं व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होती है। उन्होंने छात्राओं को योजना के अंतर्गत उपलब्ध मासिक सहायता राशि, बीमा सुविधा, अनुभव प्रमाणपत्र एवं भविष्य में बेहतर रोजगार अवसरों के संबंध में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल का प्रदर्शन कराते हुए मोबाइल क्रमांक पंजीयन, ओटीपी सत्यापन, ई-केवाईसी, प्रोफ़ाइल निर्माण एवं इंटर्नशिप आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया।

शव को सड़क पर रखकर किया विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग

बस दुर्घटना में मृत हुआ था युवक, प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बस दुर्घटना में मृत हुए युवक के परिजनों व समाजजनों ने शुक्रवार को अपना विरोध दर्ज कराया। सभी ने गांधी चौराहे पर युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों द्वारा मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने तथा बस संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। काफी देर तक प्रदर्शन व नारेबाजी के चलते मंदसौर तहसीलदार और कयामपुर टप्पा तहसीलदार रमेश मसारे भी मौके पर पहुंचे। यहां नाहरगढ़ थाना प्रभारी वरुण तिवारी भी पहुंच गए थे। कोतवाली निरीक्षक पुष्पेंद सिंह राठौड़ पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात रही। तहसीलदार ने सभी को आश्वस्त किया है। कहा कि शासन की योजना आपकी मांगे रखी जाएगी। तहसीलदार ने संबल योजना के चार लाख रुपए तत्काल खाते में ट्रांसफर कराने का भी आवस्सन दिया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोग माने और सड़क पर आंशिक जाम समाप्त हुआ।

ग्राम माल्या खेरखेड़ा के निकट निजी यात्री बस पलटने से बेटीखेड़ी गांव के 22 वर्षीय युवक वरदीचंद पिता देवीलाल मालवीय की मृत्यु हो गई थी। वह बेटीखेड़ी गांव से मंदसौर बस से आता था तथा यहां एक निजी अस्पताल में कार्य करता था। शुक्रवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में हुआ। पीएम के बाद परिजन और समाजजनों ने दुर्घटना में लापरवाही पर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में खामियां भी गिनाई। बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही एक करोड़ रुपए मुआवजा सरकार से देने की मांग रखी गई। सरकारी नौकरी की भी मांग की गई। इन मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार के समक्ष दिया गया। उधर, गांधी चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राकेश सूर्यवंशी ने कहा कि हमारे मालवीय समाज का युवक है, जिसकी बस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। मृतक वरदीचंद का परिवार गरीब है। पीएम के बाद हम सब और सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया। हमारी मांग है कि परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी, एक करोड़ा मुआवजा दिया जाए। सूर्यवंशी ने कहा कि जिस तरह से बस बगैर नियमों के सड़क पर दौड़ रही है, उनकी भी जांच की जाए। आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली उजागर होती है। बस संचालक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जग्गाखेड़ी गांव निवासी सुरेश चौहान ने कहा कि बेटीखेड़ी गांव का युवक वरदीचंद सरल स्वभाव का था। परिवार गरीब है। हमने जो मांगे रखी है, वह जायज है। बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संबंध में तहसीलदार ने कहा कि समाजजनों ने बस दुर्घटना में मृत युवक के संबंध में अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। सभी को आश्वस्त किया है।

बस चालक सहित दो पर प्रकरण दर्ज- नाहरगढ़ थाना पुलिस ने बस हादसे के मामले में ड्राइवर सहित एक अन्य पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार माल्याखेरखेड़ा के निकट हादसे में एक युवक की मृत्यु तथा 27 अन्य यात्री घायल हुए थे। एएसआई रशीद पठान की रिपोर्ट पर मुनव्वर पिता अख्तर खान नि. मंदसौर एवं सलीम पिता मुन्ना खान नि. मंदसौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

हेनरी डुनेंट का जन्म दिवस मना, मानव सेवा के लिए कार्य करती है रेडक्रॉस सोसाइटी : प्रकाश सिसौदिया

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट के जन्म की वर्षगांठ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 से मनाया जा रहा है। यह बात वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष , पूर्व डायरेक्टर श्री प्रकाश सिसोदिया ने कही। इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी डुनेंट के चित्र पर पुष्पमाला पहनाई गई व उनका स्मरण किया गया। पूर्व डायरेक्टर श्री सिसोदिया ने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है, जिसकी पूरे देश में 1200 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है, जो आपदाओं/आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करता है और कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। सिसोदिया ने कहा कि मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता ये सात मूलभूत सिद्धांत एक नैतिक, परिचालन और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का संस्थागत ढांचा है। इस अवसर पर उपस्थित अभा पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र उदिया एवं भाजपा नेता दीपक मांदलिया बसई ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर लेखपाल पुरषोत्तम भट्ट, वात्सल्य धाम प्रबंधक प्रियंका राजौरा, तनिष्का सिसोदिया, कपिल श्रीवास्तव रामप्रसाद पोरवाल, गोरधन लाल राठौर मुकेश सोनी सहित कर्मचारी उपस्थित थे।

वन विभाग ने की अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नीमच वन विभाग ने वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत लगातार तीन दिनों तक चले इस सघन अभियान में पड़दा सबरेंज की बीट मोकड़ी में कुल 12 हेक्टेयर बेशकीमती वन भूमि को अतिक्रमण के प्रयास से मुक्त कराकर सुरक्षित कर लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ ग्रामीणों द्वारा मनासा क्षेत्र की वन बीट मोकडी में अवैध रूप से कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वन विभाग के मैदानी अमले ने मौके पर पहुँचकर अतिक्रमण के इस प्रयास को पूरी तरह विफल कर दिया।

इस तीन दिवसीय कार्रवाई में 05 मई को बीट मोकड़ी के कक्ष क्रमांक 298 में 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, इसी प्रकार 06 मई को कक्ष क्रमांक 298 में 2 हेक्टेयर तथा 07 मई को कक्ष क्रमांक 297 में 6 हेक्टेयर वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया।

वन भूमि पर भविष्य में दोबारा किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके, इसके लिए विभाग द्वारा मौके पर ही जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। इस दौरान भूमि पर डबरा-डबरी कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त, वन एवं राजस्व भूमि की स्पष्ट पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीपीटी (ष्ट्क्ब्ज्ञ) की गहरी खुदाई कर एक स्थायी सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई है। यह संपूर्ण कार्रवाई वन संरक्षक, उज्जैन श्री आलोक पाठक एवं वन मंडलाधिकारी, नीमच श्री एस. के. अटोदे के निर्देशन में संचालित की गई। जिसमें उप वन मंडल अधिकारी, मनासा दशरथ अखंड के मार्गदर्शन तथा परिक्षेत्राधिकारी श्री शाश्वत द्विवेदी के नेतृत्व में परिक्षेत्र सहायक सर्वश्री नवल कुमार सिकरवार, जगदीश भास्कर, आशीष प्लास, वनरक्षक हेमंत बसेर, जगदीश परमार, अक्षय शर्मा, महेश पाटीदार, हरि सिंह चौहान, दुर्लभ सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह चौहान, मुकेश डिगा कार्यवाहक वनपाल श्रीमती ललिता शक्तावत एवं वनरक्षक श्रीमती वर्षा खींची की टीम ने वन क्षेत्र को सफलतापूर्वक अतिक्रमण मुक्त करवाया है।

साठिया बस्ती से मुक्त होगा कालाखेत क्षेत्र, सुबह नेता का निरीक्षण, शाम को प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। साठिया बस्ती से कालाखेत क्षेत्र अब मुक्त होगा। वर्षों से ये समस्या थी। लोग, व्यापारी परेशान थे। शुक्रवार को सुबह नेताजी राज्य सभा सांसद बंशीलाल गुर्जर का नपाध्यक्ष रमादेवी गुर्जर के साथ नया स्थल निरीक्षण हुआ। शाम को प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन किया गया। साठिया समुदाय को चेतावनी दी गई। संभवतः आज शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

नपाध्यक्ष रमादेवी गुर्जर ने बताया कि कई वर्षो से कालाखेत एवं उसके पास शॉपिंग कॉम्पलेक्स दया मंदिर के पीछे अस्थायी रूप से बसे हुए साठिया समुदाय को अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो इसके लिये दो तीन वर्षो से साठिया समुदाय व नपा परिषद व अन्य वरिष्ठजनों के मध्य बातचीत कर विस्थापन की प्रक्रिया चल रही थी। विगत दिनों उपयुक्त स्थान देखकर आवश्यक मूलभूत सुविधाये विकसित करने का कार्य नगरपालिका परिषद के द्वारा किया गया है। नगर पालिका व जिला प्रशासन की पहल के कारण साठिया समुदाय में विश्वास हुआ कि अब उन्हें उपयुक्त स्थान पर भूमि मिल पायेगी जहां वे सम्मानपूर्वक जीवन निर्वहन कर सकेंगे। हमारे द्वारा व वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने उन्हें लगातार समझाईश दी कि वे उपयुक्त स्थान मिलने पर उन्हें वहां निवास करना चाहिये। विगत दिनों एवं आज प्रातःकाल साठिया समुदाय के लोग मेरे निवास पर आये उनसे हमारी चर्चा हुई, हमने उन्हें समझाईश दी कि उन्हें कालाखेत छोड़कर निर्धारित स्थान पर जाना होगा। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अधिकांश लोगों ने उनके लिये निर्धारित किये हुए स्थान पर जाने पर सहमति प्रदान की। शुक्रवार को नगरपालिका की टीम ने वाहन भेजकर इनका सामान निर्धारित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया गया। लगभग 15 परिवारों ने अपना सामान समेटकर इनके लिये निर्धारित स्थान पर जाने हेतु सहमति दी है। कुछ परिवारों ने उनके लिये निर्धारित स्थान पर बसने का काम प्रारंभ कर दियाहै। नगरपालिका परिषद सभी परिवारों से अपील करती है कि वे निर्धारित स्थान पर जाकर अपना सामान रख दे और वे वही बस जाये।

नपाध्यक्ष श्रीमती गुर्जर ने निरीक्षण किया- नगरपालिका परिषद ने साठिया समुदाय को बसाने के लिये प्राप्त हुई भूमि पर अर्थवर्क, लाईनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जहां इन परिवारों को बसाने के लिये भूखण्ड दिये जायेंगे, भूखण्ड पर विस्थापित परिवारों के लोग स्थायी रूप से निवास कर सकेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर ने कल नगरपालिका की टीम के साथ यहां के अर्थवर्क, पेयजल व्यवस्था एवं लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया तथा यहां उपस्थित नगरपालिका कर्मचारियों से आवश्यक चर्चा की और उन्हें आवश्यक कार्य जल्द पुरा करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान शा. महाविद्यालय जनभागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी, भाजपा मण्डल महामंत्री अमन फरक्या, पार्षद गोवर्धन कुमावत, कमलेश सिसौदिया, आशीष गौड़ भी साथ थे। नपाध्यक्ष श्रीमती गुर्जर को नपा कर्मचारी पंकज साकी ने अवगत कराया कि विस्थापन से प्राप्त हुई भूमि पर नगरपालिका के द्वारा पेयजल की उपलब्धता के लिये हेण्डपम्प खनन किया गया है, परिवारों की सुविधा हेतु अस्थायी शोचालय भी रखा गया है तथा प्रकाश की व्यवस्था हेतु भी व्यवस्था की गई है। सभी परिवारों के यहां निवास करने पर स्थायी शौचालय एवं लाइट हेतु आवश्यक कार्य भी होंगे।

जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्णव ने की पंचायतवार कार्यो की समीक्षा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला पंचायत नीमच के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव की अध्यक्षता में ÷जल गंगा संवर्धन अभियान÷ तहत पंचायतवार संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, उपयंत्री, सचिव, रोजगार सहायक एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

समीक्षा के प्रमुख बिंदु÷ बैठक में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कार्यों जैसे तालाब गहरीकरण, पुराने जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन, जल संरचनाओं की साफ-सफाई, वर्षा जल संचयन, स्टॉप डेम निर्माण, कुओं एवं बावड़ियों के संरक्षण तथा जल संरक्षण हेतु जनजागरूकता गतिविधियों की पंचायतवार समीक्षा की गई। जिला पंचायत सीईओ श्री वैैष्णव ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए एवं ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। जिन पंचायतों में कार्यों की प्रगति धीमी है, वहां विशेष मॉनिटरिंग कर कार्यों में तेजी लाई जाए। सभी अधिकारी नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर कार्यों का निरीक्षण करें एवं प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करें। सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों से एक-एक कार्य की समीक्षा की गई।

नए एसपी राजेश व्यास का पहला एक्शन मोड, अधिकारियों को साफ संदेश - अपराध पर जीरो टॉलरेंस

रात्रि गश्त और सोशल मीडिया निगरानी पर जोर

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने पदभार संभालते ही पुलिस व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने अपराध के खिलाफ ÷जीरो टॉलरेंस÷ नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में एसपी राजेश व्यास ने सबसे पहले सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले की भौगोलिक स्थिति, थाना क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि अपराध रोकना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसपी व्यास ने महिलाओं, बच्चियों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन से पुलिस का व्यवहार सकारात्मक और भरोसेमंद होना चाहिए।

बैठक के दौरान मुख्य मार्गों, चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, प्रभावी रात्रि गश्त करने और आमजन से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अलावा लंबित अपराधों के निराकरण, थानों के रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने, एनडीपीएस मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने और साम्प्रदायिक घटनाओं की तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

एसपी ने साइबर अपराध और महिला अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने, सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने और ई-साक्ष्य आधारित विवेचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी जावद रोहित राठौर, एसडीओपी मनासा निकिता सिंह, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया सहित जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

गांधीसागर में मृत मिले तेंदुए का एनटीसीए गाइडलाइन अनुसार किया अंतिम संस्कार

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। गत 7 मई को एक वन्यजीव तेन्दुआ की मृत्यु की घटना, जिसका स्थल मुख्य सडक नीमच झालावाड वन भूमि कक्ष क्रमांक 1011 बीट चंबल नं 3 वनपरिक्षेत्र गेम रेंज पूर्व गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत प्रकाश में आई। जिस पर एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुऐ घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई। पोस्ट मार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों विशेषज्ञयों डॉ. आकाश वाल्मीक एवं डॉ. सुमित कुमार पटेल के द्वारा किया गया। वन्यजीव तेन्दुआ शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाये गये।

निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह / भस्मीकरण की कार्यवाही म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेशानुसार द्वारा गठित समिति सदस्य वृत्त उज्जैन मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन आलोक पाठक, मंदसौर वनमंडलाधिकारी संजय रायखेरे, अधीक्षक गांधीसागर अमित राठौर, नायब तहसीलदार भानपुरा सुनील अग्रवाल, गेम रेंज अधिकारी पूर्व गांधीसागर पी.एल. रायकवार, गेम रेंज अधिकारी पश्चिम गांधीसागर अभयारण्य पराग सेनानी, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीसागर मनीष परिहार की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई है। प्रकरण में वन अपराध प्रकरण क्रं. 3850/24 7 मई 2026 दर्ज कर प्रकरण में विवेचना कार्य जारी है।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आज

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में शनिवार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय नीमच तथा तहसील न्यायालय मनासा एवं जावद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

खंडपीठों का गठन- जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय नीमच में 12 खंडपीठ, तहसील न्यायालय मनासा हेतु 05 खंडपीठ तथा तहसील न्यायालय जावद हेतु 04 खंडपीठों का गठन किया गया है। निराकरण हेतु रखे गए प्रकरण- इन खंडपीठों में शमनीय आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट के चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, ट्रैफिक चालान, श्रम दावा प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व प्रकरण, विद्युत बिल संबंधी प्रकरण, जलकर संबंधी प्रकरण, बीएसएनएल के टेलीफोन बिल संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण (तलाक को छोड़कर), उपभोक्ता मामले एवं अन्य सिविल वाद आपसी समझौते एवं राजीनामे के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 854 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए हैं। खंडपीठों में पीठासीन अधिकारीगण तथा खंडपीठ सदस्यगण द्वारा पक्षकारों को आपसी समझाइश एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किए जाएंगे।

कांग्रेस के किसान जन संवाद में खोली सरकार की पोल

सरकारी गेहूं खरीदी में समस्या, भुगतान में देरी व मंडी में पानी, शौचालय, अवैध वसूली को लेकर किसान हुए मुखर

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को नई कृषि उपज मंडी में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशेष किसान जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती सहित कांग्रेस नेताओं ने सीधे किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने गेहूं खरीदी में हो रही अव्यवस्थाओं, भुगतान में देरी और मंडी परिसर की खराब व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की।

संवाद के दौरान किसानों ने सरकारी गेहूं खरीद की हकीकत बताते हुए कहा कि सरकारी खरीदी केंद्रों पर स्लॉट बुक नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपनी उपज मंडी में लानी पड़ रही है। स्लॉट बुकिंग के समय कर्मचारियों द्वारा अधिकतर सर्वर डाउन होने का बहाना बताया जाता है। उन्होंने बताया की सरकारी तौल केंद्र पर ट्रालियों को तौल के लिए चार से पांच दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें ट्रैक्टर और ट्राली का अतिरिक्त किराया देना पड़ता है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और लाभ कम होता जा रहा है। इसी कारण से वह गेहूं को कम भाव में मंडी में बेचने को मजबूर है। किसानों ने सरकार के गेहूं तौलने में कोई परेशानी नहीं हो रही इस दावे को खारिज करते हुए गेहूं समर्थन मूल्य भी बढ़ाने की मांग करी।

भावांतर राशि अटकी, व्यापारियों ने भी रखी परेशानी- किसानों ने सहकारी समितियों में गेहूं भुगतान में 15-15 दिन की देरी और भावांतर राशि लंबित रहने का मुद्दा भी उठाया। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब खाद-बीज खरीदने के समय सरकार किसी प्रकार की राहत नहीं देती, तो उपज का भुगतान भी समय पर मिलना चाहिए। वहीं व्यापारियों ने बैंकों से नकद राशि की उपलब्धता नहीं होने की परेशानी बताते हुए कहा कि किसान अपनी उपज का नगर दाम चाहता है लेकिन मजबूरी में उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करना पड़ रहा है।

रात्रि विश्राम,मंडी में पानी और शौचालय की कमी पर नाराजगी- जनसंवाद के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंडी परिसर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने मंडी परिसर में पीने के पानी और शौचालयों की कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लगभग दो किलोमीटर लंबे मंडी क्षेत्र में केवल एक सुलभ कॉम्प्लेक्स होना किसानों के साथ अन्याय है। श्री बाहेती ने मंडी सचिव को फोन पर व्यवस्था सुधारने की बात कहते हुए कहा कि किसानों की संख्या को देखते हुए कम से कम तीन सुलभ कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि दूर-दराज से आने वाले किसानों को कई बार मंडी गेट के बाहर रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मंडी अवकाश की स्थिति में किसानों को ट्रैक्टर और छोटे वाहनों में दो-दो और तीन-तीन दिन तक रुकना पड़ता है, जो बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। ऐसे में किसान रात्रि विश्राम करने की एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है साथ ही इंतजार करने वाले किसानों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त शेड भी मंडी में नहीं है। बाहेती ने सुझाव दिया कि मंडी के अलग-अलग हिस्सों में निजी कैंटीन शुरू की जानी चाहिए, ताकि किसानों को भोजन और नाश्ते के लिए भटकना न पड़े। निरीक्षण के दौरान अन्नपूर्णा भोजनालय में मिली गंदगी पर भी कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने की मांग की।

अवैध वसूली और अतिक्रमण का मुद्दा भी उठा- कार्यक्रम के दौरान किसानों ने मंडी में अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया। किसानों का आरोप था कि कुछ लोग सुबह से ही शेड के बाहर खाली ट्रालियां खड़ी कर जगह घेर लेते हैं जिस पर किसान को उपज की ट्राली खड़ी करने की जगह नहीं बाद में कुछ लोग किसानों को ट्राली खड़ी करने की जगह देने के नाम पर पैसे वसूलते हैं। इस पर तरुण बाहेती ने मंडी प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की।

अतिथि शिक्षक संघ ने उठाई मांग, अनुभव ओर वरिष्ठता के आधार पर बोनस अंक जोड़े, सोपा ज्ञापन

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेशभर के वर्षो से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण मांग उठाते हुए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के नाम नायब तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि नवीन पंजीयन प्रक्रिया में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव एवं वरिष्ठता को प्राथमिकता देते हुए प्रतिवर्षानुसार बोनस के 10 अंक स्कोर कार्ड में जोड़कर सत्र 2026-27 हेतु जारी किए जाएं।

संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक पिछले 18 वर्षो से निष्ठा, लगन और ईमानदारी से शिक्षा सेवा दे रहे हैं। ऐसे में यदि पुनः नवीन पंजीयन प्रक्रिया में पुराने अनुभवी शिक्षकों को उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। इससे उनके परिवारों का भरण-पोषण प्रभावित होगा और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पहले से पंजीकृत और अनुभव प्राप्त अतिथि शिक्षकों को नई प्रक्रिया में वरीयता दी जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में अनुभवी शिक्षकों का योगदान बना रहे। संघ ने शासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे और अपने हस्ताक्षर कर मांग का समर्थन किया।

संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।अतिथि संघ के अध्यक्ष श्री राधे श्याम धाकड़, सत्यनारायण राठौर, रितेश, संयम जैन,अभिषेक,सोनू मेव,नंदकिशोर, सिद्धार्थ जैन,उदय लाल,टीना सेन,कल्पना, शारदा पालीवाल,डिंपल विश्नोई सहित अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित थे

सम्पादकीय

क्या यूपीआई पर सब्सिडी खत्म करने का समय आ गया है?

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से मार्च 2026 में 29.5 लाख करोड़ रुपये के लगभग 22.6 अरब लेनदेन हुए। पूरे वित्त वर्ष 2026 में कुल 241.617 अरब लेनदेन हुए थे जिनका मूल्य लगभग 314.23 लाख करोड़ रुपये था।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई को एक सुरक्षित, त्वरित और अंतर-संचालनीय तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में विकसित किया था और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने 11 अप्रैल 2016 को 21 सदस्य बैंकों के साथ प्रयोग के स्तर पर इसकी शुरुआत कर दी। बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से गूगल प्ले स्टोर पर यूपीआई-सक्षम ऐप उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। उस महीने लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य के 93,000 लेनदेन हुए थे। उसी साल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई-आधारित भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप की शुरुआत की।

एनपीसीआई की सलाह से एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी अनुसंधान एजेंसी द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2021 और 2025 के बीच भारत में डिजिटल लेनदेन लगभग 11 गुना बढ़ गए जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी 80 फीसदी रही। व्यापारियों के बीच डिजिटल माध्यम से लेनदेन अब आम बात हो गई है। लगभग 94 फीसदी छोटे व्यापारियों ने यूपीआई अपना लिया है। लगभग 72 फीसदी लोगों ने डिजिटल भुगतान से संतुष्टि जताई क्योंकि इससे लेनदेन तेजी से होने के साथ ही लेखा-जोखा साफ-सुथरे तरीके से रखने में मदद मिलती है और संचालन भी आसान रहता है। 57 फीसदी ने बिक्री में बढ़ोतरी होने की बात कही।

व्यापकता, लेन-देन की रफ्तार और अंतर-संचालनीयता के मामले में दुनिया की कोई भी अन्य खुदरा भुगतान प्रणाली यूपीआई की बराबरी नहीं कर सकती। सबसे अच्छी बात यह है कि उपयोगकर्ताओं के लिए यह बिल्कुल निःशुल्क है। यह एक अनूठी वित्तीय संरचना है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और आरबीआई, दोनों का मानना है कि यह निःशुल्क ढांचा लंबे समय तक नहीं चल सकता।

भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में वही बात कही जो भुगतान उद्योग निजी तौर पर चर्चा कर रहा था। वह बात यह थी कि वर्तमान शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नीति एक स्थायी समाधान नहीं है। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले (स्ट्रीट वेंडर) और छोटे व्यवसाय को निःशुल्क सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं मगर यूपीआई के माध्यम से होने वाले बड़े वाणिज्यिक लेनदेन के लिए शुल्क लिए जा सकते हैं। डीएफएस ने संसदीय समिति के इस तर्क के पीछे आंकड़ों की पु?ष्टि की है।

सरकार फिलहाल शून्य एमडीआर लेनदेन प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बैंकों, भुगतान प्रणाली संचालकों और ऐप प्रदाताओं को मुआवजा देती है। डीएफएस ने समिति को बताया कि यह प्रोत्साहन योजना उद्योग की वास्तविक लागत के केवल 11 फीसदी हिस्से की ही भरपाई करती है। यह वर्तमान नीति के तहत उद्योग द्वारा छोड़े गए एमडीआर राजस्व का केवल 14 फीसदी ही दर्शाती है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रोत्साहन योजना के तहत किए गए आवंटन संरचनात्मक अंतर की पुष्टि करते हैं। वित्त वर्ष 2022 में लगभग 1,500 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023 में लगभग 2,600 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025 में यह तेजी से घटकर लगभग 1,500 करोड़ रुपये रह गया। इसी वित्त वर्ष रुपे डेबिट कार्ड के लिए प्रोत्साहन राशि में काफी कमी की गई थी।

आइए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में भुगतान ढांचे किस तरह काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और व्यापारियों को आपस में जोड़ते हैं और दोनों पक्ष इसमें लाभ देखते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्मों पर किए गए शोध से एक स्पष्ट मूल्य निर्धारण सिद्धांत स्थापित होता है जिसके तहत एक पक्ष से शुल्क लिया जाता है जबकि दूसरे पक्ष को सब्सिडी दी जाती है जिससे सभी के लिए यह तंत्र महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए मूल्य ढांचा महज एक संयोग नहीं है बल्कि यह निर्धारित करता है कि लागत और प्रोत्साहन साझेदारों के बीच कैसे वितरित हों। उदाहरण के लिए जीन-चार्ल्स रोशेट और जीन टिरोल द्वारा बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और दोपक्षीय बाजारों पर किए गए अग्रणी शोध से पता चलता है कि गूगल, वीजा और एमेजॉन जैसी कंपनियां विभिन्न ग्राहक समूहों से अलग-अलग कीमतें लेकर दोनों पक्षों की भागीदारी प्रोत्साहित करती हैं। यूपीआई के शुरुआती मूल्य निर्धारण ढांचे ने दोनों पक्षों को एक साथ सब्सिडी दी। इस प्रणाली को अपनाने के चरण में ऐसा करना ठीक था।

बिना किसी लागत वाली लेनदेन ने कुछ ही वर्षों में कम से कम 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं और लाखों छोटे व्यापारियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वास्तव में, शून्य-एमडीआर व्यवस्था उस समय उपयुक्त नीति थी। हालांकि, आज नीति-निर्माताओं के सामने समस्या अलग है।

हम कौन हैं? - स्वयं की खोज की एक यात्रा सहजयोग

मनुष्य सदियों से एक ही प्रश्न पूछता आया है मैं कौन हूँ? क्या हम केवल यह शरीर हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल नाम, पद, संबंध और विचारों तक सीमित है? जब जीवन में संघर्ष, तनाव, भय और असंतोष बढ़ता है, तब भीतर से एक आवाज़ उठती है क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ भी है? सहजयोग इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है स्वयं को जानने की यात्रा।

आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन भीतर से खालीपन अनुभव करता है। भौतिक प्रगति के बावजूद मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ते जा रहे हैं। स्वयं की खोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि- यह हमें आंतरिक शांति देती है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाती है, संबंधों में प्रेम और संतुलन लाती है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, सहजयोग एक सरल, स्वाभाविक और अनुभव आधारित ध्यान पद्धति है, जिसकी स्थापना श्री माताजी निर्मला देवी ने 1970 में की। सहज का अर्थ है जो जन्म से हमारे भीतर विद्यमान है, और योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सहजयोग का मुख्य उद्देश्य है आत्मसाक्षात्कार अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा, का अनुभव करना। यह केवल किसी सिद्धांत या दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जिसे हर व्यक्ति स्वयं महसूस कर सकता है।सहजयोग के अनुसार मनुष्य केवल शरीर, मन और बुद्धि नहीं है। हमारे भीतर एक सूक्ष्म चेतना विद्यमान है जिसे आत्मा कहा गया है। यही आत्मा हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। आत्मा का अनुभव ही स्वयं की खोज की पहली सीढ़ी है।

सहजयोग में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर रीढ़ की हड्डी के आधार में एक सूक्ष्म ऊर्जा स्थित होती है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। यह शक्ति हमारी आध्यात्मिक माता के समान है। जब ध्यान के माध्यम से यह जागृत होती है, तब यह हमारे सूक्ष्म चक्रों को संतुलित करते हुए सहस्रार तक पहुँचती है। इसी अवस्था में व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार का अनुभव करता है। इस अनुभव के दौरान साधक अपने हाथों और सिर के ऊपर ठंडी हवा या कंपन महसूस कर सकता है, जिसे चैतन्य लहरियाँ कहा जाता है।

जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब बाहरी परिस्थितियाँ उसे उतना विचलित नहीं कर पातीं। सहजयोग हमें यह अनुभव कराता है किन्हम केवल यह शरीर नहीं हैं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं।

हम कौन हैं? यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहजयोग इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक या तर्क से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से देता है।

प्रकृति की मूक चीखः एक पौधा हमें बचा सकता है, हम उसे बचा नहीं पा रहे

प्रकृति की गोद में रची-बसी भारतीय धरती आज भी जैव-विविधता के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, और आधुनिक वैज्ञानिक खोजें लगातार यह साबित कर रही हैं कि यह खजाना अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। हाल ही में खोजी गई पौध प्रजाति यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अभी भी अनेक अनदेखे रहस्य मौजूद हैं। यह खोज केवल एक नई वनस्पति की पहचान नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत के वन, पर्वतीय क्षेत्र और सूक्ष्म आवास विज्ञान के लिए निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट में ऐसी खोजों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि पर्यावरणीय अनुसंधान अब अधिक गहराई और विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।

मरुस्थल जैसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवन की सूक्ष्म संभावनाएँ कितनी समृद्ध हो सकती हैं, यह यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दुर्लभ पौधा आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के निगिडी वन क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों के बीच लगभग 450 से 550 मीटर की ऊँचाई पर पाया गया है, जहाँ अत्यंत कठिन जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं। फिर भी यह प्रजाति अपनी विशिष्ट जैविक संरचना के बल पर जीवित है और पर्यावरण के साथ अद्भुत संतुलन स्थापित करती है। इसकी पत्तियों और तनों की बनावट जल संरक्षण की अत्यंत उन्नत क्षमता प्रदान करती है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में भी टिकाऊ बनी रहती है। इसी असाधारण अनुकूलन क्षमता के कारण यह पौधा वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन का विषय बन चुका है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों की बढ़ती गति ने भारत की जैव-विविधता को नए आयामों में उजागर करना प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में सैकड़ों नई पौध प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि जैविक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध देश है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में हजारों नई पौध प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। केवल वर्ष 2024 में ही 410 से अधिक नई प्रजातियाँ दर्ज की गईं। इनमें अनेक प्रजातियाँ औषधीय गुणों से युक्त हैं, जो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये निरंतर हो रही खोजें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके संतुलित उपयोग की आवश्यकता को और अधिक अनिवार्य बना देती हैं।

इन दुर्लभ पौधों का अध्ययन अब केवल जैव-विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को समझने का आधार बन गया है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ दर्शाती हैं कि छोटे-से-छोटे आवासों में भी जीवन के सूक्ष्म और जटिल चक्र सक्रिय रहते हैं। यदि इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता रहा, तो अब तक अनदेखी जैव-विविधता गंभीर रूप से प्रभावित या विलुप्त हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे क्षेत्रों की सतत निगरानी और संरक्षण पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है; लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल करीब 80 पौधे ही पाए गए हैं। ग्रेनाइट खनन और जंगल की आग इसके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।

विस्तृत जैव-भौगोलिक परिदृश्य में फैले पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और दक्कन पठार आज नई प्रजातियों की खोज के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर वर्ष यहाँ होने वाली नई पहचानें यह स्पष्ट करती हैं कि वनस्पति और जीव-जगत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विज्ञान की वर्तमान समझ से बाहर है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज भी इसी निरंतर श्रृंखला का हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि सूक्ष्म स्तर पर भी प्रकृति अत्यंत जटिल और विविध संरचनाओं से बनी हुई है। ऐसी खोजें न केवल वैज्ञानिक अध्ययन को दिशा देती हैं, बल्कि नीति निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं।

इन वैज्ञानिक खोजों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से गहराई से जुड़ी होती हैं। आदिवासी और ग्रामीण समाज अक्सर ऐसे पौधों की पहचान पहले ही कर लेते हैं, जिनका औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण बाद में किया जाता है। यह सहभागिता जैव-विविधता अनुसंधान को अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाती है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसे पौधों के अध्ययन में भी स्थानीय ज्ञान की अहम भूमिका रही है, जो यह स्पष्ट करता है कि विज्ञान और परंपरा का संगम प्रकृति को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो ये खोजें केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण कई प्रजातियों को उनके दर्ज होने से पहले ही विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यदि संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जैव-विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी संदर्भ में यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी खोजें केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता का स्पष्ट संकेत भी हैं।

भारत की जैव-विविधता एक ऐसी जीवित पुस्तक है, जिसके नए अध्याय हर वर्ष खुलते जा रहे हैं। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ यह प्रमाण देती हैं कि प्रकृति अभी भी अपने रहस्यों को हमारे सामने धीरे-धीरे उजागर कर रही है। आवश्यकता है कि इस ज्ञान को केवल संग्रहित न किया जाए, बल्कि संरक्षण और सतत विकास में प्रभावी रूप से अपनाया जाए। यदि इन अनमोल प्राकृतिक खजानों की रक्षा समय रहते नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें केवल पुस्तकों और संग्रहालयों तक सीमित पाएंगी। हमारी जैव-विविधता जितनी समृद्ध है, उतनी ही नाजुक भी है, इसलिए इसका संरक्षण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

-प्रो. आरके जैन

लो हम भी असामाजिक हो गए

मोहल्ले के जमुनालाल जी आजकल अत्यंत चिंतित हैं। चिंता भी ऐसी वैसी नहीं राष्ट्रीय स्तर की है। फर्क बस इतना है कि राष्ट्र की शुरुआत उनके घर के ड्रॉइंग रूम से होती है और अंत उनके मोबाइल की बैटरी से।

आज सुबह-सुबह ही वे गली के मोड़ पर मिल गए। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे लोकतंत्र उन्हीं के भरोसे चल रहा हो और अभी-अभी किसी ने उसे अनफ्रेंड कर दिया हो। मुझे देखते ही दहाड़े

लो आ गए! तुम लोग ही हो जो इस समाज को खा गए हो! मैंने घबराकर इधर-उधर देखा कहीं और कोई तो नहीं जिसे वे दोष देना चाहते हों पर दुर्भाग्य से मैं ही अकेला शिकार था क्या हुआ जमुनालाल जी? मैंने पूछा।

वे बोले क्या हुआ? अरे, सोशल मीडिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया! रिश्ते खत्म, समाज खत्म, आदमी खत्म अब बस मोबाइल बचा है! मैंने सोचा, इतनी बड़ी तबाही अगर सच में हो गई होती तो कम से कम न्यूज चैनलों को तो खबर होती, पर वहाँ तो अभी भी बहस चल रही है कि देश में असली मुद्दा क्या है। जमुनालाल जी बिना रुके बोले जा रहे थे पहले क्या जमाना था! लोग बिना बुलाए घर आ जाते थे! मैंने मन में कहा हाँ, और बिना पूछे ही खाना भी खा जाते थे, और जाते-जाते बर्तन भी गिन जाते थे। वे बोले अब देखो, बेटा अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठा रहता है, बहू इंस्टाग्राम में लगी है, बेटी रील बना रही है, दामाद ट्विटर पर क्रांति कर रहा है कोई किसी से बात ही नहीं करता!

मैंने पूछा तो आप उनसे बात करते हैं- वे थोड़ा सकपकाए, फिर बोले हम क्यों बात करें? हम बड़े हैं न! हमें कोई पूछे तो हम बोलें! यानी संवाद की जिम्मेदारी भी अब लोकतंत्र की तरह दूसरे पर डाल दी गई है।

जमुनालाल जी की असली पीड़ा यह थी कि अब कोई उनके पास बैठकर उनकी लंबी-लंबी बातें नहीं सुनता। पहले लोग शिष्टाचार में फँस जाते थे अब मोबाइल के बहाने बच निकलते हैं। उन्होंने दुखी स्वर में कहा अब कोई मिलने भी नहीं आता रिश्तेदार बुलाते भी नहीं।

मैंने सोचा पिछली बार जब उनके रिश्तेदार आए थे, तब जमुनालाल जी ने उन्हें चाय देने से पहले 'भारत में सामाजिक पतन' पर 50 मिनट का भाषण दिया था। चाय ठंडी हो गई, रिश्ते भी।।वे बोले हम तो अब समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहे! मैंने मन ही मन कहा जमुनालाल जी, समाज ने आपका मुँह देखना बंद नहीं किया है बस अब लोग स्क्रीन देखना ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं।

देखो, ये फेसबुक! यहाँ लोग नकली जिंदगी जीते हैं! मैंने देखा उनकी खुद की प्रोफाइल फोटो 15 साल पुरानी थी, जब वे 20 किलो हल्के और 30 साल छोटे थे।

मैंने पूछा ये फोटो कब की है- वे बोले अरे, वही जब असली जमाना था! मतलब, सच वही है जो उन्हें अच्छा लगे,बाकी सब नकली है। जमुनालाल जी का दुख यह नहीं है कि समाज टूट रहा है। उनका दुख यह है कि अब समाज उनकी सुविधा के अनुसार नहीं चल रहा। पहले लोग उनके पास बैठकर मजबूरी में हाँ-हाँ करते थे।

-संजीव ठाकुर

बंगाल की हिंसा है लोकतंत्र पर धब्बा और बड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, किंतु जब यह उत्सव हिंसा, भय और प्रतिशोध में बदल जाए तो यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। बंगाल की ताजा हिंसक घटनाएं इसी चिंता को सामने लाती हैं। चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था। लेकिन परिणामों की घोषणा के बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हुए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक संघर्ष न रहकर प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें, कई लोगों की हत्याएं और विशेष रूप से सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह क्यों बची रहनी चाहिए?

यह विडंबना है कि भारत, जिसने विश्व को अहिंसा, करुणा और ÷वसुधैव कुटुम्बकम्÷ का मंत्र दिया, आज वही देश राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी छवि धूमिल करता दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता और सेवा से जोड़ा था, लेकिन आज राजनीति सत्ता, प्रतिशोध और भय का माध्यम बनती जा रही है। बंगाल की हिंसा इस बीमारी का एक भयावह उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा से अछूता नहीं रहा है। वामपंथी शासन के लंबे दौर से लेकर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल तक राजनीतिक संघर्ष कई बार रक्तरंजित रूप में सामने आया। बूथ कब्जाने, विरोधियों को डराने, स्थानीय दबंगों और अपराधी तत्वों का राजनीतिक संरक्षण-ये सब बंगाल की राजनीति की कटु वास्तविकताएं रही हैं। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद भी हिंसा का वातावरण बनता है और आम नागरिक भय तथा असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर होता है।

दरअसल जब राजनीति विचार और जनसेवा से हटकर केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम बनती है। हार को लोकतांत्रिक विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध का माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और विजय जुलूसों पर प्रतिबंध के बावजूद हिंसक घटनाएं हुईं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की नैतिक विफलता भी है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाना और राजनीतिक टकराव को तीखा बनाना हो या भाजपा द्वारा आक्रामक राजनीतिक प्रतिक्रिया-दोनों पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को शांति और संयम का संदेश दें। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दल अक्सर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उकसाने का काम करते हैं। परिणामस्वरूप हिंसा सामान्य राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है।

सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक हिंसा की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के घर जलते हैं, जिन परिवारों के सदस्य मारे जाते हैं, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें टूटती हैं, उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल उस हिंसक मानसिकता के शिकार बनते हैं जो सत्ता को मानवता से ऊपर मानती है। यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? जबकि इतिहास गवाह है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं देती। हिंसा केवल भय, अविश्वास और प्रतिशोध को जन्म देती है। जो दल हिंसा को हथियार बनाते हैं, वे अंततः जनता की नजरों में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं।

आज भारत एक नए वैश्विक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी महाशक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देख रही है। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे सभ्य और नैतिक राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए जहां राजनीति का आधार अहिंसा, संवाद और संवेदनशीलता हो। यदि राजनीतिक दल नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा को अपना हथियार बनाए रखेंगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना रही है। गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, महावीर ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया, गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सह-अस्तित्व है। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थों और गैर-राजनीतिक आपराधिक तत्वों के कारण देश की छवि प्रभावित हो रही है। अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे दल बदलते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति और स्वार्थ की पूर्ति होता है। बंगाल की ताजा घटनाओं में भी ऐसे तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

समाधान केवल प्रशासनिक कठोरता में नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन में निहित है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता का नहीं, सह-अस्तित्व का नाम है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर ÷जीरो टॉलरेंस÷ की नीति अपनानी होगी। किसी भी दल से जुड़े उपद्रवियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बढ़ानी होगी। तीसरा, राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में प्रवेश ही न मिले जिनकी पृष्ठभूमि हिंसक और आपराधिक रही हो। राजनीतिक दलों को अपने भीतर नैतिक अनुशासन विकसित करना होगा। चैथा, समाज में लोकतांत्रिक शिक्षा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में संवाद, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। जब तक समाज स्वयं हिंसा को अस्वीकार नहीं करेगा, तब तक राजनीतिक हिंसा का अंत कठिन होगा।

बंगाल की ताजा हिंसा केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है। यदि हमने समय रहते राजनीति को स्वस्थ मूल्यों की ओर नहीं मोड़ा, तो नफरत और हिंसा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने। यह देश युद्ध और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि शांति, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भूमि है। ÷वसुधैव कुटुम्बकम्÷ केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का मूल दर्शन है। यदि राजनीति इस दर्शन से विमुख होगी, तो लोकतंत्र केवल सत्ता संघर्ष बनकर रह जाएगा। पश्चिम बंगाल को अब हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही लोकतंत्र की गरिमा है, यही जनता की अपेक्षा है और यही विकसित भारत का मार्ग भी।

-ललित गर्ग

सोमनाथ भारत की अपराजित आत्मा का प्रतीक, पीएम मोदी ने विरासत और आस्था को बताया राष्ट्र की शक्ति

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है- प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।

यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर, 1947 को दीवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर, 2001 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया।

11 मई, 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं।

पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है।

-धनंजय राजौरा

कलेक्टर और निगम आयुक्त ने बिलावली स्थित 12 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया औचक निरीक्षण

प्लांट परिसर में बेहतर रखरखाव और सुरक्षा मानकों का पालन करने के दिए निर्देश

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नगर निगम कमिश्नर दलीप कुमार के साथ बिलावली स्थित 12 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, जल शुद्धिकरण की तकनीक और संसाधनों के रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर संजीव जैन, तहसीलदार श्रीमती सपना शर्मा सहित अन्य नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं नगर निगम कमिश्नर दलीप कुमार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। उन्होंने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और टेस्टिंग मानकों की जानकारी ली गई। सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर टैंक का निरीक्षण कर यह समझा गया कि किस प्रकार गंदे पानी को प्रोसेस कर उसे पूरी तरह साफ किया जाता है। उन्होंने प्लांट में लगे विभिन्न मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की कार्यक्षमता को परखा।

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निर्देशित किया कि प्लांट का संचालन पूरी क्षमता और गुणवत्ता के साथ निरंतर जारी रहे, ताकि जल संरक्षण के साथ-साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उन्होंने प्लांट परिसर में बेहतर रखरखाव और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 लाख लीटर (2 एमएलडी) पानी उपचारित किया जा रहा है। इस शोधित जल का उपयोग मुख्य रूप से आस-पास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर के विभिन्न उद्यानों और पौधों में पानी डालने के लिए इस स्वच्छ जल का प्रयोग हो रहा है।

निरीक्षण के दौरान एलसी इंफ्रा के प्लांट इंचार्ज ने प्लांट की पूरी प्रोसेस से अवगत कराया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं नगर निगम कमिश्नर ने ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम के माध्यम से पूरे प्लांट की कार्यप्रणाली को देखा। इस सिस्टम के जरिए प्लांट के हर सेक्शन की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग डिजिटल रूप में की जा रही है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है।

शनिवार को लोक अदालत मे बकाया संपत्तिकर व जलकर जमा कराने पर मिलेगी छूट

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। 9 मई शनिवार को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि पर नियमानुसार लोक अदालत में मिलेगी छूट। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने इस संबंध मे बताया कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत में जिन संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादरों द्वारा संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा नही की है वे अपना बकाया कर जमा कर लगने वाला सरचार्ज (अधिभार) मे छूट का लाभ लें। महापौर ने बताया कि लोक अदालत के दिवस करदाताओं की सुविधाओं हेतु निगम कार्यालय के साथ ही जवाहर चौक एवं ईटावा बस स्टेण्ड झोन कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में भी कर जमा करने हेतु शिविर लगाये गये हैं। लोक अदालत के दिवस निगम कार्यालय में कर जमा कराने का समय प्रातः 9 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा। नागरिकों के लिए बैठने एवं पीने के पानी की सुविधा रहेगी। महापौर ने निगम सीमा क्षेत्र के करदाताओं से अपील की है कि वे शनिवार को आयोजित लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कर सरचार्ज (अधिभार) मे मिल रही छूट का लाभ अवश्य लें।

विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो - ऊर्जा मंत्री श्रीतोमर

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को उप नगर ग्वालियर बिरला नगर पुल से चंदन पुरा तक जनकल्याण समिति के सहयोग से सुपर सकर मशीन द्वारा चल रहे सीवर सफाई अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बारिश से पहले इस काम को हर हाल में पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जहां-जहां नवीन सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है वहां गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर की स्वच्छता को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए सीवर समस्या के समाधान के लिए सुपर सकर मशीन द्वारा सफाई का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था और अधिक तेज, प्रभावी व सुदृढ़ बनेगी। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने उपनगर ग्वालियर में आ रहे बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, सड़क, खेलकूद, शिक्षा हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ग्वालियर स्वच्छता के मामले में नंबर एक बनाने के प्रयास करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्वच्छता, सुविधा और बेहतर जीवन स्तर बनाना हमारा संकल्प है। मंत्री श्री तोमर के निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद गण उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सकरवट गांव में लगाई ग्राम चौपाल जमीन में बैठकर ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं

रीवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा जनपद के ग्राम सकरवट में देर शाम ग्राम चौपाल लगाई तथा जमीन में बैठकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं। ग्रामवासियों ने भी अपनत्व भाव से कलेक्टर को एक-एक कर गांव की समस्याएं बताईं जिनका कलेक्टर ने समाधान कारक निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने व जमीनी हकीकत को परखने के लिए सीधे संवाद करने मैं आपके गांव आया हूँ। आप बेहिचक अपनी सभी समस्याएं बता सकते हैं ताकि गांव में संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा सके और लोगों को इनका लाभ मिल सके।

ग्राम चौपाल कार्यक्रम में सकरवट के रहवासियों ने गांव में सड़क की समुचित व्यवस्था न होने की ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया तथा कहा कि राजस्व रिकार्ड में सड़कों को दर्ज कराया जाए साथ ही सुमेदा तक सड़क निर्माण करा दिया जाए। उन्होंने गांव की मुख्य सड़क को खोदकर अवरोध पैदा करने के कारण हो रही समस्याओं की ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया। ग्रामवासियों ने ट्रांसफार्मर का सुधार कराने, बनकुइयाँ बांध का सुधार कराने तथा खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्धता की मांग भी रखी। गांव वासियों ने आंगनवाड़ी के नियमित नहीं खुलने की भी बात कलेक्टर से कही तथा गांव में दो अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की मांग की। ग्रामवासियों ने गांव में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध कलेक्टर से किया। कलेक्टर ने ग्रामवासियों को आश्वस्त करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी के नियमित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की उपस्थिति नियमित करें तथा आशा कार्यकर्ता भी अपना कार्य ठीक ढंग से करें। उन्होंने विद्यालय में शौचालय का सुधार कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए।

अमलतास मेडिकल कॉलेज में 77 वर्षीय श्री जीवनलाल का देहदान संकल्प पूरा

भावी डॉक्टरों को मिला अमूल्य योगदान

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मानवता की मिसाल पेश करते हुए, श्री जीवनलाल नायक (उम्र 77 वर्ष) का देहदान करने का प्रेरणादायक संकल्प सोमवार, 29 अप्रैल , 2026 को अमलतास मेडिकल कॉलेज, देवास में संपन्न हुआ।

यह पुनीत कार्य सेवाधाम आश्रम, ग्राम अम्बोदिया, जिला उज्जैन के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत श्री सुधीर भाई गोयल जी के प्रयासों से पूरा हुआ। उन्होंने स्व. जीवनलाल जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी पार्थिव देह को कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में दान किया।

इस कड़ी में देवास पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ. ए.के. पीठवा ने सम्मान स्वरूप आभार व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की । एवं इस अवसर पर कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव शरीर की संरचना का ज्ञान आवश्यक है, और शरीर दान भावी चिकित्सकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह अमूल्य सहयोग विद्यार्थियों के व्यावहारिक अध्ययन और चिकित्सा विज्ञान के ज्ञानार्जन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।देहदान अधिकारी श्री गजानंद चौहान जी ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी। अमलतास मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन मयंकराज सिंह भदौरिया ने इस प्रेरक पहल के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। डीन डॉ. ए.के. पीठवा, एनाटॉमी विभाग हेड डॉ. करखायले एम.एल., और अमलतास समूह ने संस्था सेवाधाम आश्रम के प्रति कृतज्ञता जाहिर की।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बदमाश विकास तिवारी की निरोध अवधि तीन माह बढ़ाई

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। विदिशा जिले के निवासी एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाश विकास तिवारी पुत्र इन्द्रजीत प्रसाद तिवारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध अवधि को आगामी तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अवर सचिव अन्नू भलावी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विकास तिवारी वर्ष 2008 से लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध मारपीट, चोरी, हत्या का प्रयास, अवैध शराब बिक्री तथा अवैध हथियार रखने एवं उपयोग करने जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। शासन के अनुसार उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि गोपनीय सूचनाओं एवं स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई है कि निरोध से मुक्त होने पर वह पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर जिले की कानून व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उसके रिहा होने की स्थिति में जनसामान्य के जीवन एवं सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है।

प्रशासन को यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्न संगठनों एवं मध्यप्रदेश अभिभाषक संघ द्वारा भी उक्त बदमाश के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। शासन ने लोकतंत्र, लोकहित एवं राष्ट्रहित में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देते हुए निरोध अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकास तिवारी की निरोध अवधि 4 मई 2026 से आगामी 3 माह अर्थात 4 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है।

बारिश से पहले दुरुस्त हों सीवर लाइनें, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई - अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइनों, मैनहोल और सीवर चेंबरों की मरम्मत बारिश से पहले हर हाल में पूरी की जाए। शहरवासियों को वर्षाकाल में सीवर संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने गुरुवार को नगर निगम के विकास कार्यों एवं एलिवेटेड रोड परियोजना की समीक्षा बैठक में दिए। बाल भवन स्थित एक्यूआई सेंटर में आयोजित बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री संकेत भोंडवे, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री दिव्यांक सिंह व अपर आयुक्त नगर निगम श्री टी प्रतीक राव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने स्पष्ट रूप से कहा कि एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए स्वर्णरेखा नदी में डाली गई मिट्टी तत्काल हटाई जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सीवर लाइन और चेंबरों की मरम्मत में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि वर्तमान एजेंसी कार्य करने में सक्षम नहीं है तो नई एजेंसी या वेंडर को तत्काल जिम्मेदारी सौंपी जाए। संबंधित अधिकारी दो दिन के भीतर यह सुनिश्चित करें कि कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य पर होने वाला व्यय संबंधित ठेकेदार के भुगतान से समायोजित किया जाए।

बैठक में एलिवेटेड रोड परियोजना के फेस-1 एवं फेस-2 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। फेस-1 के अंतर्गत सीवर समस्या के समाधान की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फेस-2 के ठेकेदार को 30 मई तक आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। शहर की सीवर व्यवस्था पर चर्चा के दौरान आरईपीएल कंपनी के प्रतिनिधि संतोषजनक कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कंपनी की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए। जीआईएस मैपिंग के माध्यम से विभिन्न वार्डों में सीवर समस्याओं की समीक्षा की गई तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित समाधान के लिए प्रस्तावों और टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यक कार्यों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए तथा स्मार्ट सिटी के खाली बैठे इंजीनियरों की सेवाएं नगर निगम के कार्यों में ली जाएं।

वार्डो में स्वच्छता बनी रहे इस हेतु आयुक्त कर रहे हैं सतत वार्डो का निरीक्षण

निगम ने पुलिस प्रशासन के सहायोग से हटाया सडको से अस्थाई अतिक्रमण

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वार्ड 17 व 18 में आयुक्त दलीप कुमार ने वार्डो की स्वच्छता व्यवस्था देखी, वार्डो मे आयुक्त ने भ्रमण के दौरान नाला एवं नालियों की सफाई व्यवस्था देखी जिसमे स्वच्छता निरीक्षकों को वर्षा पूर्व नालों की सफाई तथा वार्ड क्षेत्रों में नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए वहीं कुछ स्थानों पर खुले स्थानों पर कचरा पाए जाने पर तत्काल कचरा उठाने के साथ ही खुले मे कचरा डाले से रहवासियों से सतत सम्पर्क कर जागरूक करने हेतु कहा।

उपायुक्त देखें अपने झोन एरिया में स्वच्छता के कार्यो को–आयुक्त- आयुक्त के निर्देशानुसार सभी उपायुक्त अपने अपने झोन एरिये में स्व्चछता सर्वेक्षण के मानक स्तर पर होने वाली साफ सफाई व्यवस्था को सतत देख रहे है तथा जो कमियां उसे दरोगा एवं स्वच्छता निरीक्षकों से निराकरण करवा रहे हैं। उपायुक्त जाकिर जाफरी द्वारा व्यवसाईक क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए किये जा रहे कार्यो को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर कार्य करवाने के साथ ही उसका भौतिक सत्यापन भी उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है।

बस स्टेण्ड मेन रोड के दोनो तरफ का हटाया अस्थाई अतिक्रमण- इसी प्रकार निगमायुक्त दलीप कुमार के निर्देशन में निगम की टीम द्वारा शहर के स्वच्छ वातावरण एवं सुगम यातायात हेतु जिला एवं निगम प्रशासन के साथ अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई। जिसके अन्तर्गत बस स्टेण्ड मुख मार्ग एबी रोड पर सडक के दोनो ओर वाहन पार्किंग एवं अन्य अस्थाई अतिक्रमण हटाये जाने की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की ओर से एडिशनल एस.पी. एच.एन. बाथम, यातायात निरीक्षक पवन बागरी एवं सुबेदार राहूल चंदेल, सब इंस्पेक्टर भगवानसिहं सहित 36 का पुलिस बल जिसमें महिला एवं पुरूष सहित निगम से निगम उपयंत्री विजय जाधव, श्याम सुन्दर रघुवंशी, अतिक्रमणटीम प्रभारी हेमन्त उबनारे, प्रतिक शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक विजय सांगते एवं निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अस्थाई अतिक्रमणों मे रखी सामग्री निगम द्वारा तथा यातायात बाधित जगह से पार्किंग से बडी मात्रा में टुव्हीलर एवं अन्य वाहन पुलिस द्वारा जप्त किये गये। हटाये गये अतिक्रमण एवं पार्किंग स्थलों पर पुनः अतिक्रमण किया गया तो सामग्री जप्त कर भारी मात्रा मे चालानी कार्रवाई की जावेगी।

अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने एलिवेटेड रोड, नाला सफाई और मल्टीलेवल पार्किंग का किया निरीक्षण

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने गुरुवार को ग्वालियर शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन, नाला सफाई व्यवस्था एवं महाराज बाड़ा स्थित मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बारिश से पहले सीवर संधारण एवं नालों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। यदि बारिश के दौरान शहर में जलभराव या सीवर ओवरफ्लो की समस्या सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री संकेत भोंडवे, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री दिव्यांक सिंह, अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव व श्री प्रदीप तोमर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने सबसे पहले एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन के संधारण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मरम्मत कार्य बारिश शुरू होने से पहले पूर्ण किए जाएं और कहीं भी सीवर लाइन ओवरफ्लो की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिये सर्वोच्च प्राथमिकता से सीवर समस्या का स्थायी समाधान समय पर सुनिश्चित करें। श्री दुबे ने नाला सफाई कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रमुख नालों की सफाई अभियान स्तर पर कराई जाए, ताकि वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

भ्रमण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने इसके बाद महाराज बाड़ा स्थित मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि अतिवर्षा के कारण भूजल स्तर बढ़ने से तलघर में पानी भर गया है। वर्तमान में तलघर में लगभग आठ फीट पानी जमा होने के कारण पार्किंग का उपयोग प्रभावित हो रहा है। इस पर श्री दुबे ने तलघर से निकल रहे पानी के सदुपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इस पानी का उपयोग जनहित में किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने चेतकपुरी क्षेत्र के नाले एवं सड़क का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नाले के आसपास निर्माण सामने आने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित प्रकरण की फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर बिलावली स्थित 12 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया औचक निरीक्षण

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने नगर निगम कमिश्नर श्री दलीप कुमार के साथ बिलावली स्थित 12 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, जल शुद्धिकरण की तकनीक और संसाधनों के रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक?टर श्री संजीव जैन, तहसीलदार श्रीमती सपना शर्मा सहित अन?य नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह एवं नगर निगम कमिश्नर श्री दलीप कुमार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। उन?होंने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और टेस्टिंग मानकों की जानकारी ली गई। सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर टैंक का निरीक्षण कर यह समझा गया कि किस प्रकार गंदे पानी को प्रोसेस कर उसे पूरी तरह साफ किया जाता है। उन?होंने प्लांट में लगे विभिन्न मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की कार्यक्षमता को परखा।

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने निर्देशित किया कि प्लांट का संचालन पूरी क्षमता और गुणवत्ता के साथ निरंतर जारी रहे, ताकि जल संरक्षण के साथ-साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उन?होंने प्लांट परिसर में बेहतर रखरखाव और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 लाख लीटर (2 एमएलडी) पानी उपचारित किया जा रहा है। इस शोधित जल का उपयोग मुख्य रूप से आस-पास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर के विभिन्न उद्यानों और पौधों में पानी डालने के लिए इस स्वच्छ जल का प्रयोग हो रहा है।

निरीक्षण के दौरान एलसी इंफ्रा के प?लांट इंचार्ज ने प्लांट की पूरी प्रोसेस से अवगत कराया। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह एवं नगर निगम कमिश्नर ने ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम के माध्यम से पूरे प्लांट की कार्यप्रणाली को देखा। इस सिस्टम के जरिए प्लांट के हर सेक्शन की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग डिजिटल रूप में की जा रही है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है।

खबर नहीं, हकीकत का आइना, चिलचिलाती धूप में कतारों का दर्द, आखिर कौन लेगा इसकी सुध

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। यह लोकतंत्र की कैसी तस्वीर है? एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर बदनावर की मयोरा गैस एजेंसी पर अपनी ही बुनियादी जरूरतों के लिए जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। शुक्रवार को जो मंजर दिखाई दिया, उसने न केवल मानवता को शर्मसार किया, बल्कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के जनसेवा के दावों की भी पोल खोलकर रख दी।

शुक्रवार को आसमान से आग बरस रही थी, लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। इस जानलेवा गर्मी में सैकड़ों ग्रामीण और नगरवासी गैस सिलेंडर के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे। विडंबना देखिए, जिस जनता के वोट से कुर्सी चमकती है, उसी जनता के लिए न वहां छाया का टेंट था और न ही कंठ तर करने के लिए पानी की एक बूंद। सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि जब जनता भीषण गर्मी में तड़प रही थी और एजेंसी प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतारू था, तब न तो कोई आला अधिकारी अपनी एसी वाली गाड़ी से बाहर निकला और न ही किसी माननीय जनप्रतिनिधि ने जनता का दर्द बांटने की जहमत उठाई। आखिर ये जिम्मेदार अधिकारी किस बात का वेतन ले रहे हैं? क्या जनता को केवल कतारों में खड़े रहने और अपमान सहने के लिए छोड़ दिया गया है?

एजेंसी प्रबंधन और कर्मचारियों की बदसलूकी से जनता का सब्र अब टूट चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, उपभोक्ताओं ने सरेआम कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। जनता का सीधा सवाल है– आम आदमी के लिए नो स्टॉक और चहेतों के लिए पीछे के दरवाजे से सिलेंडर कैसे उपलब्ध हो रहे हैं? कर्मचारियों का अड़ियल रवैया और संचालिका की चुप्पी क्या किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है?

बदनावर की जनता अब इस धमकाऊ और लापरवाह तंत्र को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि यदि तत्काल प्रभाव से सुधार नहीं हुआ और दोषी कर्मचारियों व एजेंसी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह आक्रोश जल्द ही आंदोलन की लपटों में बदल जाएगा। क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार कर रहा है, या इस मामले को गम्भीरता से लेगा। जनता के यह भी है सवाल की क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव के समय हाथ जोड़ने तक सीमित है या इस जनता के हक़ के लिए आगे आने के लिए।

किठौर आंगनवाड़ी केंद्र पर स्तनपान कार्यशाला का आयोजन

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सलसलाई शुक्रवार को ग्राम किठौर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती और धात्री माताओं के लिए एक विशेष स्तनपान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और माताओं को सही पोषण तकनीकों से अवगत कराना था।

कार्यशाला के मुख्य बिंदु- सही तकनीक का प्रदर्शन- कार्यशाला में उपस्थित माताओं को बच्चों को स्तनपान कराने की सही पोजीशन और बच्चों की स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया गया।

डकार का महत्व- शिशुओं को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाने की सही विधि और इसके फायदों पर विस्तृत चर्चा की गई।

चिकित्सकीय सलाह- विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यदि माता या बच्चे में किसी भी प्रकार की शारीरिक जटिलता दिखाई दे, तो तुरंत शासकीय चिकित्सक से सलाह लें और उचित उपचार हेतु रेफरल प्रक्रिया अपनाएं।

गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति-

इस महत्वपूर्ण सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई-

बलवीर मेवाड़ा- कॉमन सर्विस सेंटर प्रतिनिधि

नारायण सिंह- अमूल्य दूध डेयरी फार्म, खेड़ावद

किरण परमार- प्रभारी परियोजना अधिकारी

ग्राम पंचायत सदस्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

कार्यशाला के अंत में उपस्थित माताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें बच्चों के शुरुआती 6 महीनों में केवल स्तनपान कराने के संकल्प के साथ विदा किया गया।

बदनावर का कायाकल्प, एक किमी तक बनने वाले नालों से मिलेगी जलजमाव और गंदगी से मुक्ति

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के विकास और स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत बड़नगर रोड से महाराणा प्रताप चौक तक आदर्श सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ हो चुका है। लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाले इन डेढ़-डेढ़ मीटर के नालों से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा।

उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर लंबे समय से जलजमाव और कीचड़ के कारण गंदगी का आलम बना हुआ था, जिससे स्थानीय रहवासी और राहगीर खासे परेशान थे। क्षेत्र के नागरिकों ने इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव को कई बार अवगत कराया था। रहवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष श्रीमती यादव ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा और त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया था। कार्य प्रारंभ होने के साथ ही वह आश्वासन साकार होता नजर आ रहा है। इस निर्माण कार्य के पूर्ण होते ही रहवासियों को लंबे समय से व्याप्त गंदगी और जलजमाव की समस्या से स्थायी रूप से निजात मिल जाएगी। नाला निर्माण के साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि आगामी कुछ ही दिनों में मुख्य सड़क का निर्माण कार्य भी तेजी से प्रारंभ किया जाएगा। यह विकास कार्य न केवल क्षेत्र को सुगम आवागमन प्रदान करेगा, बल्कि बेहतर यातायात सुविधा और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम से क्षेत्र का कायाकल्प होगा। नगर परिषद अध्यक्ष ने इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नगर का समग्र विकास और जनता की समस्याओं का निराकरण ही हमारी पहली प्राथमिकता है।

प्रगणकों ने केवल 8 दिन मे पूरा किया जनगणना कार्य, तहसीलदार ने किया सम्मानित

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सीहोर तहसील ग्रामीण चार्ज में कार्यरत 02 प्रगणकों श्री विनोद कुमार त्यागी और श्री रूपसिंह वर्मा ने उत्कृष्ट कार्य कुशलता का परिचय देते हुए मात्र 08 दिनों में ही में ही अपने कार्यक्षेत्र में मकान सूचीकरण का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर एक सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस प्रतिबद्धता, परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए तहसीलदार डॉ अमित सिंह द्वारा उन्हें फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया।

इसके साथ ही तहसीलदार डॉ अमित सिंह ने बताया कि सीहोर नगर तहसील ग्रामीण चार्ज अंतर्गत भी जनगणना के प्रथम चरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इस उपलब्धि के लिए प्रगणक श्री धीरज एवं सुपरवाइजर श्री बृजेश शर्मा को सम्मानित किया गया। इन प्रगणकों द्वारा कम समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति न केवल अन्य प्रगणकों के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यदि जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य किया जाए तो निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य 01 मई से 30 मई तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं और निर्धारित प्रपत्रों में परिवारों की आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी दें और जनगणना में सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के समुचित वितरण एवं विकास योजनाओं की बेहतर योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्राम पंचायत होलीपुरा में जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिला सीहोर द्वारा ÷जल गंगा संवर्धन अभियान÷ के अंतर्गत विकासखंड बुधनी की ग्राम पंचायत होलीपुरा में जल संरक्षण एवं संवर्धन विषयक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण कृषकों एवं आमजन को जल संरक्षण के महत्व, वर्षा जल संचयन तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम ग्राम पंचायत होलीपुरा के सरपंच श्री कमल सिंह ओझा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सरपंच श्री ओझा ने जल को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ग्रामवासियों से जल स्त्रोतों के संरक्षण, तालाबों एवं कुओं के पुनर्जीवन तथा जल के समुचित उपयोग के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

कार्यशाला में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों को जल संरक्षण के व्यावहारिक उपायों, फसल जल प्रबंधन तथा उद्यानिकी फसलों में जल उपयोग दक्षता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों को खेत स्तर पर जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, फार्म पॉन्ड तथा वर्षा जल संचयन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान किसानों को बताया गया कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग से कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही भू-जल स्तर को संरक्षित रखने में भी सहायता मिलती है। किसानों ने कार्यशाला में रुचिपूर्वक भाग लेते हुए जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

फेसबुक पर छाया भारती का जलवा

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सोशल मीडिया के इस दौर में जनता से जुड़ाव और लोकप्रियता के मामले में धार जिले ने पूरे मध्य प्रदेश में बाजी मारी है। हाल ही में जारी फेसबुक फॉलोअर्स की ताजा सूची ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता का सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास धार के जिला अध्यक्ष को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की फेसबुक सक्रियता और लोकप्रियता के आधार पर तैयार की गई टॉप-10 सूची में धार जिला अध्यक्ष निलेश भारती प्रथम स्थान पर रहे हैं। 51 हजार से अधिक फॉलोअर्स के साथ वे प्रदेश के अन्य दिग्गज जिलों जैसे इंदौर, ग्वालियर और सागर के अध्यक्षों से काफी आगे निकल चुके हैं। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारती की सक्रिय कार्यशैली और जनता के बीच उनकी मज़बूत पकड़ का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर उनके प्रति लोगों का यह रुझान दर्शाता है कि वे न केवल संगठन के कार्यों में सक्रिय हैं, बल्कि आम जनमानस की समस्याओं और संवाद के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉ

नवागत पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने ग्रहण किया आगर मालवा जिले का पदभार

आगर मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शुक्रवार को नवागत पुलिस अधीक्षक आगर मालवा दिलीप कुमार सोनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आगर मालवा पहुंचकर विधिवत रूप से जिले के पुलिस अधीक्षक पद का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार बोयट, एसडीओपी आगर मोतीलाल कुशवाहा, एसडीओपी सुसनेर देवनारायण यादव, थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय, निरीक्षक अनिल कुमार मालवीय, निरीक्षक हीना कनेश, प्रभारी रक्षित निरीक्षक जगदीश यादव,सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नवागत पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने तथा आमजन के प्रति संवेदनशील, प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनसुरक्षा एवं जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु निर्देशित किया।

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिले की समीक्षा बैठक आयोजित

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जनकल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूर्ण करें। शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा जनसमस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी मंत्री श्री चौहान शुक्रवार को सर्किट हाउस आगर-मालवा में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नाबाई चौहान, विधायक मधु गेहलोत, जिलाध्यक्ष ओम मालवीय भी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों के मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क खुदाई के कारण नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य बारिश पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। इस दौरान उन्होंने एलएनटी कंपनी द्वारा ग्रामों में सड़क खुदाई के बाद समय पर मरम्मत कार्य नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत, सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण कर बरसात पूर्व सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए स्लॉट बुकिंग, बारदाना उपलब्धता, परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो तथा खरीदी केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कृषकों की उपज की समय पर तुलाई एवं निर्धारित समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर स्लॉट बुकिंग, भंडारण एवं परिवहन की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

बैठक में बताया गया कि जिले में 42 खरीदी केन्द्रों पर उपार्जन कार्य संचालित किया जा रहा है। अब तक 20 हजार 843 कृषकों से गेहूँ उपज खरीदी जा चुकी है। जिले के कृषकों की उपज की शीघ्र तुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम कंकड़ेल में 30 हजार मैट्रिक टन क्षमता का सायलो बैग स्थापित किया गया है, जहां अब तक 13 हजार 617 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समयावधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अटल गृह ज्योति योजना एवं अटल किसान ज्योति योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी तथा जिले में संचालित ग्रिड निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि एलटी लाइन बिछाने के दौरान संबंधित विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए। मजरे-टोलों में विद्युत समस्याओं के निराकरण हेतु सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नवीन ग्रिड स्वीकृति के बाद शीघ्र सर्वे कर प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा गया।

प्रभारी मंत्री श्री चौहान ने ग्रीष्म ऋतु में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं पर सतत निगरानी रखी जाए तथा समस्या की जानकारी मिलने पर अधिकारी तत्काल क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब एवं सुधार योग्य हैंडपंपों को शीघ्र दुरुस्त करने तथा नए हैंडपंपों की मांग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से जल योजना की प्रगति की समीक्षा कर कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में संचालित अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण कराने पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री श्री चौहान ने जनगणना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा, सीईओ जिला पंचायत बी.एस. सोलंकी, एसडीएम किरण बरबड़े, डिप्टी कलेक्टर कमल मंडलोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों के हक की लड़ाईः 7 मई को चक्का जाम आंदोलन

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में देपालपुर विधानसभा से किसानों की समस्याओं को लेकर 7 मई को ए बी रोड मेडिकैप्स चौराहा पीगडंबर पर चक्का जाम आंदोलन किया इस आंदोलन में इंदौर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल के नेतृत्व में देपालपुर विधानसभा से ट्रैक्टर, फोर व्हीलर, और टू व्हीलर के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ओर किसान शामिल हुए।

किसान नेता मोतीसिंह पटेल ने बताया कि किसानों की फसल गेहूं का समर्थन मूल्य पर समय पर नहीं तोलना, आलू, प्याज, लहसन के बाजार में भाव नहीं मिलने, सरकार की गलत नीतियों के कारण सहकारी बैंकों में किसान डिफाल्टर हो गए हैं।

सरकार द्वारा आने वाले समय में किसानों को प्रति बीघा एक बोरी खाद ई टोकन के माध्यम देंगे और किसानों की समय पर फसल नहीं खरीदी जाने प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता को समाप्त किया जा रहा है दुग्ध उत्पादक किसानों को ?5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी 2 वर्ष से अधिक भी जाने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया है। बरलाई शुगर मिल की जमीन किसानों को उचित मुआवजा दिए बिना उद्योगपतियों को दे दी गई आगामी समय में बतलाई शुगर मिल पर भी किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस नेता द्वारा आदि मुद्दों को उठाया।

जिन किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल कम दाम पर मंडियों में बेच दी है उनको भावांतर की राशि दी जाए। नहीं तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में बेटमा ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी सत्यनारायण जाट हातोद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनेर सिंह सोलंकी उमराव सिंह मौर्य मलिक खान जीतू दरबार प्रकाश पटेल बाबू सिंह पटेल गुलाब सिंह पटेल विष्णु मंडलोई जितेंद्र सिंह ठाकुर आजम खान देवकरण गुर्जर जगदीश भावसार मोहन चौधरी राजेश बड़वाया निलेश पवार यशवंत राठोर लक्ष्मण तोतला रफीक पठान रवि पटेल अमित पटेल दिलीप पटेल हर्षित खंडेलवाल मुकेश पटेल धर्मेंद्र पटेल छतर पटेल पोप सिंह मालवी दिनेश नगर राजेंद्र कोठारी अर्जुन खत्री गब्बर पटेल राम प्रसाद पवार दिनेश यादव राजीव यादव भगवान सिंह सरपंच लोकेश सिसोदिया सुरेश यादव शाहिद बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

काला जी महाराज के दरबार में भंडारे का आयोजन संपन्न

निशान यात्रा मैं श्रादलुओ का उमड़ा जनसैलाब

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मदाना गांव के जंगल स्थित चमत्कारी काला जी गोरा जी महाराज का देवस्थान है यहां प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया था सुबह 9 बजे से ही भगवान काला जी गोरा जी के मंदिर में आरती प्रारंभ हो चुकी थी साथ ही 10 बजे गांव इलाई माता मंदिर परिसर से देव दरबार के पंडाजी द्वारा निशान यात्रा भी निकली गई थी उक्त निशान यात्रा गांव के प्रमुख मार्ग होकर तिगजपुर रोड स्थित गोपचान वाले जंगल में गोरा जी कल जी महाराज के मंदिर परिसर पहुंची निशान यात्रा में गाय माता भी मौजूद थी जहां सभी देव पंडा ने गाय माता की पूजा अर्चना की सुख संपत्ति के लिए कामना की मंदिर परिसर पहुंचने के बाद बैठक आयोजित की गई सभी देव महाराज के पड़ा जी द्वारा भविष्यवाणी भी की गांव के सैकड़ो श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे हर कोई बाबा की जय जयकार करते हुए दिखाई दिए जहां काला जी महाराज के पंडा द्वारा सभी श्रद्धालुओं को गंगाजल की छाट लगाकर उनकी समस्या का समाधान किया जिसके तपश्रात भोजन प्रसादी का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया भंडारे के आयोजन में ग्राम मदाना सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र तिगजपुर सिलेपूर गोलाना सारंगपुर सलसलाई खरसोदा चापडिया आदि गांव के श्रद्धालु भी शामिल हुए थे मंदिर समिति के धीरज सिंह जी सिसोदिया ने बताया कि यहां बाबा के चमत्कारी दरबार में हम प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन करवाते हैं यह ग्राम मदाना सहित दूर-दूर तक श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है यहां आज भी कहीं चमत्कार देखने को मिलते हैं की बात कहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाईन निविदाओं का आंमत्रण लोक निर्माण विभाग में 'सी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रतिशत आधार, आईटम रेट आधार एवं लमसम आधार पर किया जाता हैं।

नि.स.क्रं .	प्रपत्र का प्रकार	कार्य का विवरण	कार्य की अनु लागत	प्रतिभूति राशि	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र का मूल्य	पमयावधि	निविदा क्रय की अंतिम तिथि	दर प्रस्तुत करने की अंतिमतिथि
2026_UAD_504623_1	2.10	क्षिप्रा शुद्धिकरण अंतर्गत सीवर पाईप लाईन व चेम्बरों की सफाई कार्य।	1565851/-	31350/-	2000/-	12 माह	01.06.2026	01.06.2026

निविदा संबंधित अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा सूचना की जानकारी वेब साईट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाईन दर्शाई गई हैं।

कार्यपालन यंत्री
सीवरेज ,नगर पालिक निगम

आयुक्त
नगर पालिक निगम उज्जैन

सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। संसदीय क्षेत्र रतलाम की सांसद श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं आधारभूत सुविधाओं की विभागवार समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने सभी विभागों को योजनावार एवं क्रमवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में स्वीकृत 1233 खेत तालाबों में से 260 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें 30 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में 4071 डगवेल रिचार्ज कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2244 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य 15 मई तक पूर्ण किए जाएंगे। इसी प्रकार 14 अमृत सरोवरों में से 2 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें 30 मई तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अन्य 1368 जल संरक्षण संरचनाओं में से 518 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

सांसद श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान ने जिले में जल संकट की समस्या के स्थायी समाधान हेतु जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाबोर ने नवीन चेक डेम निर्माण का सुझाव दिया। अन्य जनप्रतिनिधियों ने निस्तार तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संधारण कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 147 अमृत सरोवर निर्मित किए गए हैं तथा अमृत 2.0 के तहत 14 अतिरिक्त सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 147 अमृत सरोवरों में 112 में वर्तमान में पानी उपलब्ध है। सांसद ने समस्त जनप्रतिनिधियों को अमृत सरोवरों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को समय पर राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

कृषि विभाग- उप संचालक कृषि श्री एन.एस. रावत ने जिले के कृषि रकबे, आगामी खरीफ सीजन के लिए प्रस्तावित रकबा, संभावित उत्पादन, उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में नगदी फसलों, दलहनों एवं तिलहनों का रकबा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

उन्होंने ई-विकास प्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधियों से किसानों को जागरूक करने एवं इस प्रणाली के प्रचार-प्रसार में सहयोग करने की अपील की। सांसद श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन कर किसानों को ई-विकास प्रणाली के संबंध में जानकारी दी जाए। उन्होंने जिले में जल संकट की स्थिति को देखते हुए सूखा प्रतिरोधी फसलों एवं कम पानी की आवश्यकता वाली किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाबोर ने ई-विकास प्रणाली के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का सुझाव दिया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग- कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री जितेन्द्र मावी ने बताया कि जिले में कुल 14,888 हैंडपंप स्थापित हैं, जिनमें से 10,349 में पर्याप्त जल उपलब्ध है। 1,748 हैंडपंपों में जल की कम आवक है तथा 2,791 हैंडपंप जल अभाव के कारण बंद हैं। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित 617 नल-जल योजनाओं में से 529 चालू हैं जबकि 88 योजनाएं बंद हैं, जिनमें से 42 योजनाएं जल स्त्रोत सूखने के कारण प्रभावित हैं।

सांसद श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि कम आवक वाले 1,748 हैंडपंपों में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रिचार्ज पिट का निर्माण कराया जाए। साथ ही पीएचई विभाग द्वारा जल स्त्रोतों एवं हैंडपंपों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाध्यक्ष श्री भानु भूरिया ने तकनीकी खराबी की स्थिति में मैकेनिकों की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाते हुए पर्याप्त संख्या में मैकेनिक उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। बैठक में जल निगम द्वारा पेटलावद एवं धमोही जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 992 सड़कों, जिनकी कुल लंबाई 723.05 किलोमीटर है, में से 181 सड़कों (लगभग 60 किलोमीटर) के डीपीआर तैयार करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। विधायक थांदला श्री वीरसिंह भूरिया ने क्षतिग्रस्त ग्वाली ब्रिज के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य का विषय उठाया।

महाप्रबंधक ने जानकारी दी कि पूर्व में निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण संबंधित अनुबंध निरस्त कर दिया गया था तथा वर्तमान में पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगतिरत है।

जनगणना 2027 के तहत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रगणकों का सम्मान

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर परिषद सुसनेर में जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं भवन गणना (एचएलबी) का कार्य प्रगणकों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में ब्लॉक क्रमांक 0004 के प्रगणक नंदकिशोर नागर, ब्लॉक क्रमांक 0017 के प्रगणक संतोष जादमे एवं ब्लॉक क्रमांक 0020 के प्रगणक शिवलाल दांगी द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

उत्कृष्ट कार्य पूर्ण होने पर जनगणना चार्ज अधिकारी एवं सीएमओ ओपी नागर द्वारा कार्यालय में प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का सम्मान किया गया। इस दौरान एचएलबी 0004 के सुपरवाइजर पुनीत शुक्ला, एचएलबी 0020 के सुपरवाइजर गिरिराज पाटीदार तथा एचएलबी 0017 के सुपरवाइजर विक्रम मालवीय को भी बधाई दी गई।

चार्ज अधिकारी ओपी नागर ने कहा कि जनगणना कार्य शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा इसे पूरी जिम्मेदारी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि राणा चितरंजन सिंह, नगर परिषद के कर्मचारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय परिसर का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आज कलेक्टर कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने परिसर में पीने के पानी के वाटर कूलर एवं पानी निकासी की सम्पूर्ण व्यवस्था करने , पानी का भराव ना हो , परिसर एवं शौचालय में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने भू अभिलेख कक्ष का निरीक्षण किया, कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अभिलेख को व्यवस्थित रखनें के लिए प्लानिंग करे एवं प्रस्ताव बनाया जा कर विभाग को प्रेषित करे।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराये राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में किया जायेगा। लोक अदालत के संबंध में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष बड़वानी श्री महेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन ने बताया गया कि 09 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 864 एवं प्रिलिटिगेशन 4115 प्रकरण रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिले में कुल 18 खण्डपीठो का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत छुट, जलकर छुट सम्पत्तिकर छुट दी जायेगी। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी। ऽ प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

नवोदय से निकलकर डॉक्टर बने सारोला के लवकेश पाटिल, MBBS फाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बुरहानपुर जिले के ग्राम सारोला निवासी किसान रविन्द्र (छोटू) पाटिल के परिवार के लिए गर्व का क्षण उस समय आया, जब परिवार के होनहार बेटे डॉ. लवकेश पाटिल ने MBBS की फाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर गांव एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया। लवकेश, प्रकाश पाटिल, योगेश पाटिल एवं राहुल पाटिल के भतीजे हैं। उनकी इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है।

डॉ. लवकेश पाटिल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे लवकेश ने कठिन मेहनत और लगन के दम पर नीट परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्हें देवास स्थित अल्तमश मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए प्रवेश मिला। मेडिकल की कठिन पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने निरंतर मेहनत जारी रखी और अब MBBS की फाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

लवकेश की सफलता की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों एवं शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने उन्हें मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गांव के लोगों ने भी इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए डॉ. लवकेश पाटिल प्रेरणास्त्रोत बनकर उभरे हैं।

परिजनों ने बताया कि डॉ. लवकेश का सपना भविष्य में समाज सेवा करते हुए जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उनकी सफलता से ग्राम सारोला सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का वातावरण बना हुआ है।

विधि विशेषज्ञ बी.एस. रावत ने योजनाओं के क्रियान्वयन का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनजातीय प्रकोष्ठ लोक भवन, भोपाल से विधि विशेषज्ञ श्री बी.एस. रावत जिले में कृषि, उद्यानिकी एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों को मिल रहे वास्तविक लाभ एवं व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान श्री रावत ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत संचालित इकाइयों का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राम दौलतपुरा निवासी श्री निलेश डामोर द्वारा संचालित आइसक्रीम यूनिट का निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया, मशीनरी, गुणवत्ता नियंत्रण एवं विपणन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वरोजगार आधारित इस इकाई की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण बताया।

इसके साथ ही श्री रावत ने ग्राम मानपुर में कृषक श्री रसु मडिया के खेत पर स्थापित ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं कृषक श्री हमु मडिया के अमरूद उद्यान का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान रोजगार सृजन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग, फसल संरक्षण एवं उत्पादन वृद्धि के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री रावत ने किसानों को नवाचार आधारित तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक कृषि पद्धतियां किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने फसल बीमा योजना के हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के लाभ, आ रही समस्याओं एवं विभागीय सहयोग के संबंध में फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके।

निरीक्षण उपरांत श्री बी.एस. रावत ने उद्यानिकी विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों एवं युवाओं को विभागीय योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य किया जाए। इस अवसर पर सहायक संचालक उद्यान श्री बहादुरसिंह चौहान, सहायक संचालक कृषि श्री हिरासिंह चौहान, जिला समन्वयक श्री अर्पित भूरिया सहित कृषि एवं उद्यानिकी विकासखंड के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशनः गांधीसागर-2 योजना की पानी टंकी में मामूली लीकेज प्रारंभिक टेस्टिंग अवधि का, सुधार कार्य प्रगतिरत महाप्रबंधक जल निगम ने दी जानकारी

उपसंग्रामपुर ग्राम की टंकी से वर्तमान में 4 गांवों में की जा रही है जलापूर्ति

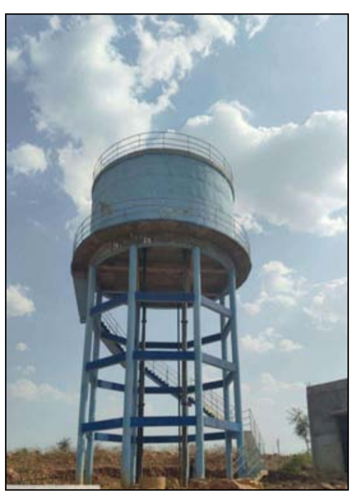

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में लीकेज होने संबंधी प्रकाशित समाचार के संबंध में म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई नीमच द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है।

महाप्रबंधक धीरेंद्र कुमार बिजोरिया ने बताया कि गांधीसागर-2 समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत दाता अमरपुरा के उपसंग्रामपुर ग्राम में टंकी का निर्माण कार्य किया गया है। वर्तमान में गांधीसागर-2 समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत टेस्टिंग कार्य प्रगतिरत है।

वस्तुस्थिति- उक्त के संबंध में सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संबंध में महाप्रबंधक जल निगम नीमच द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है उन्होंने बताया कि उक्त टंकी के वर्टिकल पाईप के जॉइंट में जो लीकेज पाया गया है, वह प्रारंभिक टेस्टिंग अवधि* में आता है। टेस्टिंग के दौरान पाई जाने वाली ऐसी मामूली कमियों का सुधार कार्य तुरंत ही किया जाता है। वर्तमान में वर्टिकल पाईप में मामूली लीकेज है जिसका सुधार कार्य प्रगतिरत है।

जलापूर्ति जारी- महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उक्त टंकी से 4 गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। टेस्टिंग पूर्ण होने के उपरांत योजना को अंतिम रूप से संचालित किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, बड़नगर जिला-उज्जैन म.प्र.

E-mail:-cmobadnagar@mpurban.gov.in phone no.: 07367-226060

क्रमांक-917/निर्माण/ईटेण्डरिंग/2026 बडनगर दिनांक :- 07/05/26

: ई-निविदा आमंत्रण सूचना :

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइड https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लगत	निविदा प्रपत्र का मुल्य एवं ईएमडी	निविदा की अतिम तिथी
1	2	3	4	5	6
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5054 82_1	वार्ड क्रं. 03 की विभिन्न गलियों में आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 2756989.00/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 5000/-EMD मुल्य 20700/-	05.06.2026
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5054 86_1	वार्ड क्रं. 05 नयापुरा में सीसी रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 2583241.5/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 5000/-EMD मुल्य 19500/-	05.06.2026
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5054 93_1	वार्ड क्रं.05 पंढरीनाथ कुंड में सीसी रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 2409521.5/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 2000/-EMD मुल्य 19100/-	05.06.2026
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5055 01_1	वार्ड क्रं. 07 में सीसी रोड निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 2921172.5/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 5000/-EMD मुल्य 22000/-	05.06.2026
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5055 05_1	वार्ड क्रं. 10 कैलाश माली के मकान से डायवर्शन रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 1586220.0/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 2000/-EMD मुल्य 11900/-	05.06.2026
912/ 05.05. 2026	2026_UAD_5055 07_1	वार्ड क्रं. 01 काजीपुरा, उत्सव घाट, खारी बावडी तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	कार्य की समयावधि 30 दिन लागत 7476090.5/-	निविदा प्रपत्र मुल्य 10000/- EMD मुल्य 37400/-	05.06.2026

नोट:-

1- विस्तृत निविदा टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं बाउनलोड करने के लिये https://www.mpetenders.gov.in वेबसाईड पर सुविधा उपलब्ध है अधिक जानकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद् बडनगर में देखी जा सकती है।

2-निविदा डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार नगर पालिका परिषद बड़नगर में उपलब्ध शर्तों का अवलोकन करने को पश्चात ही टेण्डर क्रय करें।

3-निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, उसके लिये पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा।

4-शासन निर्देशानुसार जी.एस.टी. की समस्त शर्ते लागू होगी।

श्री अभय टोग्या, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् बड़नगर | श्रीमति अनिता सतीश वर्मा, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् बड़नगर | श्रीमती लक्ष्मीबाई लालबहादुर बाहदशाह, निर्माण सभापति, नगर पालिका परिषद् बड़नगर | श्री एम.आर. निगवाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बड़नगर

राष्ट्रपति भवन से मिला सम्मान, नीमच के युवा कलाकार राहुल लोहार ने बढ़ाया जिले का मान, महामहिम राष्ट्रपति ने भेजा हस्ताक्षरित आधिकारिक छायाचित्र और प्रशंसा संदेश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश के नीमच जिले के छोटे से ग्राम कुंचड़ोद के युवा चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने अपनी अद्भुत कला प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी कला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान राष्टपति भवन से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है।

राहुल कुमार लोहार द्वारा महामहिम राष्टपति द्रौपदी मुर्मू को समर्पित 'नारी शक्ति' विषयक भावपूर्ण चित्रकला ने राष्टपति भवन का ध्यान आकर्षित किया। कलाकार की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्टपति सचिवालय ने उन्हें महामहिम का हस्ताक्षरित आधिकारिक छायाचित्र एवं प्रशंसा पत्र भेजा है। यह सम्मान किसी भी युवा कलाकार के लिए बेहद गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

चित्र में दिखी नारी शक्ति की प्रेरक अभिव्यक्ति- राहुल ने अपनी कलाकृति में राष्टपति द्रौपदी मुर्मू को भारतीय नारी शक्ति, आत्मविश्वास, संघर्ष और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह चित्र राष्टपति भवन, नई दिल्ली भेजते समय महामहिम के हस्ताक्षरित छायाचित्र की इच्छा भी व्यक्त की थी। राष्टपति सचिवालय द्वारा उनकी भावना का सम्मान करते हुए आधिकारिक उत्तर भेजा गया, जिसने इस उपलब्धि को और विशेष बना दिया।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय पहचान तक का सफर- ग्राम कुंचड़ोद जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाना राहुल कुमार लोहार की मेहनत, रचनात्मक सोच और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनकी यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे नीमच जिले और मध्यप्रदेश की कला-संस्कृति के लिए गर्व का विषय बन गई है।

प्राकृतिक माध्यमों से बनाई कला ने पहले भी बटोरी थी सुर्खियां- राहुल कुमार लोहार इससे पहले भी अपनी नवाचारी कला शैली को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी माताजी के चित्र गोबर, मेथीदाना तथा प्राकृतिक रंगों जैसे पारंपरिक माध्यमों से बनाकर व्यापक सराहना प्राप्त की थी। उनकी कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति, सामाजिक संदेश और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक कर चुके हैं सराहना- राहुल की कला प्रतिभा की सराहना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इससे उन्हें लगातार प्रोत्साहन और नई पहचान मिली।

राष्टपति भवन से प्राप्त यह सम्मान अब क्षेत्र के युवा कलाकारों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरा है। राहुल कुमार लोहार ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, ग्रामवासियों और कला प्रेमियों के आशीर्वाद को दिया है।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

उज्जैन में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन... प्रशासन को सोमवार तक अल्टीमेटम

जिला बदर अशोक जाट के समर्थन में कलेक्टोरेट पहुंचे विधायक और कांग्रेसी बोले- मंडियों की अव्यवस्था उठाई तो प्रशासन ने कार्रवाई कर दी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक जाट पर हुई जिला बदरी की कार्रवाई अब राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की थी, लेकिन इंदौर के पूर्व विधायक अश्विनी जोशी के निधन की सूचना मिलते ही आंदोलन को सांकेतिक रूप देकर आधे घंटे का मौन प्रदर्शन किया गया।

कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। हाथों में विरोध के संकेत और चेहरों पर नाराजगी लिए नेताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई को किसानों की आवाज दबाने की कोशिश बताया।विधायक महेश परमार ने साफ कहा कि अशोक जाट ने लगातार मंडियों, उपार्जन केंद्रों और किसानों की परेशानियों को उठाया। इसके बदले प्रशासन ने उन पर जिला बदरी की कार्रवाई थोप दी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो सोमवार से आंदोलन उग्र रूप ले सकता है।

सोमवार से फिर शुरू होगा धरना- कांग्रेस ने प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार सुबह 11 बजे से विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठेंगे। कांग्रेस इसे किसान सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रही है।

छह जिलों समेत उज्जैन से बाहर रहने का आदेश- दरअसल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक जाट को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक उन्हें उज्जैन के अलावा देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार और आगर मालवा की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। हालांकि आदेश में यह राहत दी गई है कि यदि किसी न्यायालय में उनके प्रकरण लंबित हैं, तो वे पेशी की तारीख पर संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देकर जिले में प्रवेश कर सकेंगे। पेशी पूरी होने के बाद तुरंत क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा।

किसानों के हक की लड़ाई की सजा- नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आरोप लगाया कि अशोक जाट लगातार समर्थन मूल्य, गेहूं खरीदी और उपार्जन केंद्रों की गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस का दावा है कि यही सक्रियता प्रशासन को नागवार गुजरी और जिला बदरी की कार्रवाई कर दी गई।

कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताते हुए कहा कि यदि किसानों के मुद्दे उठाने वालों को अपराधी की तरह पेश किया जाएगा तो प्रदेशभर में आंदोलन होगा।

जिला बदरी किन परिस्थितियों में होती है- हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक जिला बदरी की कार्रवाई तब की जाती है जब पुलिस और प्रशासन की रिपोर्ट में यह आशंका जताई जाए कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों से शांति भंग हो सकती है या आमजन में भय और अशांति का वातावरण बन रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन सीमावर्ती जिलों से भी निष्कासन का आदेश जारी कर सकता है।

अशोक जाट पर दर्ज प्रकरण- अशोक जाट पर अब तक कई मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कुछ में वे दोषमुक्त हो चुके हैं और कुछ न्यायालय में लंबित हैं–

-वर्ष 2008 ¬ धारा 312 – दोषमुक्त

-वर्ष 2017 ¬ धारा 294 – दोषमुक्त

-वर्ष 2017 ¬ किसान आंदोलन से जुड़ा सामूहिक प्रकरण, 22 लोगों पर एफआईआर; मामला न्यायालय में अंतिम चरण में

-वर्ष 2026 ¬ धारा 155 का मामला, अभी थाने स्तर पर, चार्जशीट पेश नहीं

कांग्रेस का कहना है कि पुराने और विचाराधीन मामलों को आधार बनाकर किसान नेता को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दलील दे रहा है। उज्जैन की राजनीति में यह मामला अब सीधे किसान बनाम प्रशासन की लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है।

हादसों पर रेलवे की सख्ती... अब पटरियां फांदीं तो रास्ता बंद

सिंहस्थ से पहले उज्जैन की खुली रेलवे लाइनें होंगी कवर, 5 किमी तक बनेगी बाउंड्रीवॉल

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। ट्रेन पकड़ने की जल्दी हो या शॉर्टकट का लालच, अब रेलवे ट्रैक फांदकर निकलना आसान नहीं रहेगा। शहर के चारों ओर खुली पड़ी रेलवे पटरियों को पश्चिम रेलवे बाउंड्रीवॉल बनाकर पूरी तरह कवर करने जा रहा है। रेलवे ने इसकी शुरुआत नईखेड़ी क्षेत्र से कर दी है, जहां ट्रैक के दोनों ओर करीब साढ़े तीन फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है।

रेलवे का फोकस सिर्फ हादसे रोकना नहीं, बल्कि सिंहस्थ-2028 की विशाल भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालना भी है। योजना के तहत उज्जैन स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर तक सभी प्रमुख रूटों पर पटरियों के दोनों किनारों को कवर किया जाएगा। इसके बाद लोग सीधे ट्रैक पार नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज या अंडरपास का ही सहारा लेना पड़ेगा।

इन रूटों पर होगा सबसे ज्यादा फोकस- रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उज्जैन-पंवासा और इंदौर रूट पर विक्रमनगर तक का हिस्सा प्राथमिकता में रखा गया है। यहां बड़ी संख्या में लोग रोजाना ट्रैक पार करते हैं। कई बार जल्दबाजी में लोग सीधे ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। मवेशियों और आवारा जानवरों के ट्रैक पर पहुंचने से भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बाउंड्रीवॉल बनने के बाद इन घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी।

सिंहस्थ की भीड़ संभालने की तैयारी- रेलवे सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर अभी से सुरक्षा ढांचा मजबूत कर रहा है। ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में पिंगलेश्वर, विक्रमनगर, नईखेड़ी और चिंतामण स्टेशन को होल्डिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यहां श्रद्धालुओं को उतारकर आगे भेजा जाएगा। ऐसे में लाखों लोगों की आवाजाही के दौरान ट्रैक पार करने जैसी घटनाएं सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। रेलवे इसी खतरे को खत्म करने की तैयारी में जुटा है।

अब नहीं चलेगा 'शॉर्टकट'- अभी शहर के कई हिस्सों में लोग समय बचाने के लिए सीधे ट्रैक पार करते हैं। स्कूल-कॉलेज के छात्र, नौकरीपेशा लोग और आसपास की बस्तियों के रहवासी रोजाना यही जोखिम उठाते हैं। कई बार रेलवे की चेतावनी और अभियान के बावजूद लोग नहीं मानते। रेलवे का मानना है कि बाउंड्रीवॉल बनने के बाद ट्रैक तक पहुंच ही बंद हो जाएगी, जिससे हादसों में बड़ी कमी आएगी।

2027 तक पूरा होगा काम- पश्चिम रेलवे के पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया कि हादसे रोकने के लिए ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है। नईखेड़ी क्षेत्र में काम शुरू हो चुका है और सिंहस्थ से पहले वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प से शिप्रा के पवित्र जल से संत और श्रद्धालु करेंगे सिंहस्थ में स्नान

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संकल्पना से सिंहस्थ महापर्व पर शिप्रा नदी में शिप्रा के साफ-स्वच्छ जल से स्नान होगा। शुक्रवार को संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना और जीवन खेड़ी से सिकंदरी तक सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ महापर्व के लिए कान्ह डायवर्शन योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना को समय सीमा में करने के लिए रात और दिन कार्य कर पूर्ण किया जाए। संभागायुक्त श्री सिंह ने जीवन खेड़ी से सिकंदरी तक निर्माणाधीन सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण के दौरान बड़े आकार के पौधे मार्ग के दोनों ओर लगाने के निर्देश दिए, जिससे मार्ग का कार्य पूर्ण होने के बाद पूरा मार्ग ग्रीन होकर सुंदर लगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प से विश्व स्तरीय अलौकिक सिंहस्थ 2028 महापर्व के दौरान साधु-संत और विश्व भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु निर्मल साफ स्वच्छ मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से स्नान करेंगे। कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित जल को उज्जैन शहर में शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है।

कंचनपुरा में उपद्रव मचाने वाले बदमाश का निकाला जुलूस

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कंचनपुरा में बुधवार गुरुवार रात कुछ बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया था और एक मकान में तोड़फोड़ करने के साथ महिलाओं से मारपीट करते हुए वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में लेने के बाद उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला जहां उसने साथियों के साथ बवाल किया था। कंचनपुरा में जुलूस निकाला।

माधव नगर थाना क्षेत्र के कंचनपुरा में रहने वाले भागीरथ रायकवार के मकान पर आधी रात को ढांचा भवन क्षेत्र के रहने वाले गोलू उर्फ पप्पू रायकवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर तोड़फोड़ की थी और परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बावल में भागीरथ की पुत्री पूजा और 75 साल की मां भगवती बाई के साथ रिश्तेदार महिला और युवक घायल हो गए थे। कंचनपुरा में बदमाशों के उपद्रव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उपद्रव करने

वाले बदमाश भाग निकले थे लेकिन पुलिस ने पीछा कर गोलू उर्फ पप्पू के साथ एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में आए गोलू उपद्रव का मुख्य आरोपी होना सामने आया था जिसका पुलिस ने शाम को कंचनपुरा क्षेत्र में जुलूस निकाला और रात में फैलाई गई दहशत को लोगों के बीच बीच से काम किया। बदमाश गोलू कान पकड़कर माफी मांगता रहा। थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले बदमाश को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा उसके नाबालिग साथियों से पूछताछ कर अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोलू कंचनपुरा में रहने वाले आईटीआई में सदस्य भागीरथ के पड़ोस में रहने वाले परिवार का जमाई है। भागीरथ का पड़ोसी से पिछले 2 साल से विवाद चल रहा है जिसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है उसी मामले में गोलू ने अपने नाबालिग साले और साथियों के साथ मिलकर भागीरथ के घर पर उपद्रव किया था।

चिंतामण बायपास पर विरोध.... किसानों के साथ गुरुकुल के बटुक भी उतरे सड़क पर

रेलवे के नए सर्वे का विरोध तेज, ग्रामीण बोले- खेती, आश्रम और गांव की पहचान मिटाने की साजिश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के बहुप्रतीक्षित चिंतामण बायपास प्रोजेक्ट को लेकर अब गांवों में विरोध की आग तेज हो गई है। शुक्रवार को मंगरोला रोड पर किसानों, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने रेलवे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि विरोध प्रदर्शन में वैदिक गुरुकुल के बटुक भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर परियोजना का विरोध जताया।

ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे विभाग पहले ही इस परियोजना का सर्वे और नक्शा तैयार कर किसानों की जमीनें चिन्हित कर चुका था, लेकिन अब दोबारा सर्वे के नाम पर क्षेत्र में खंभे गाड़े जा रहे हैं और जमीन का नया चिन्हांकन किया जा रहा है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि प्रस्तावित चिंतामण बायपास बनने से मंगरोला सहित आसपास के कई गांव सीधे प्रभावित होंगे। किसानों के मुताबिक अकेले मंगरोला गांव के करीब 38 किसानों की जमीन इस परियोजना की जद में आ रही है, जबकि करीब 40 से 50 बीघा कृषि भूमि प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल जमीन अधिग्रहण का मामला नहीं, बल्कि गांव की जीवनरेखा और वर्षों पुरानी पहचान बचाने की लड़ाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बायपास की जद में स्कूल, वेद आश्रम, चिंतामण और मंगरोला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, बाग-बगीचे और कई छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आ जाएंगे। किसानों का कहना है कि यदि यह योजना लागू हुई तो गांव का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने रेलवे को वैकल्पिक सुझाव भी दिया। उनका कहना है कि शिप्रा केबिन क्षेत्र की ओर से कम दूरी और कम लागत वाला अंडरपास मार्ग तैयार किया जा सकता है, जिससे किसानों की जमीन और धार्मिक-सामाजिक संस्थाएं प्रभावित होने से बच जाएंगी।

किसान दीपक, जीत सिंह फौजी और सूर्यपाल सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

वहीं अखिल भारतीय नागदा अग्निहोत्री धर्मशाला में संचालित वैदिक गुरुकुल के संचालक आचार्य दीपक पाठक ने भी योजना पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धर्मशाला परिसर में देश के अलग-अलग राज्यों से आए 25 से 50 बटुक वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि बायपास का निर्माण इसी मार्ग से किया गया तो गुरुकुल का शांत वातावरण और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी।

ग्रामीणों और किसानों का साफ कहना है कि विकास के नाम पर गांवों की जमीन, धार्मिक संस्थाएं और किसानों की आजीविका कुर्बान नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल चिंतामण बायपास का मुद्दा अब प्रशासन और रेलवे के लिए नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है।

पांच डेरों पर पुलिस का रातभर सर्च ऑपरेशन, 147 से ज्यादा हिरासत में

25 से अधिक बाइक जब्त, 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई; कई जिलों में वारदात से जुड़े होने की आशंका

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने गुरुवार रात बड़ा अभियान चलाया। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बने पांच संदिग्ध डेरों पर एक साथ दबिश देकर 147 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान 25 से अधिक दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए, जिनके दस्तावेज और स्वामित्व की जांच की जा रही है।

पुलिस ने जिन स्थानों पर कार्रवाई की, उनमें कार्तिक मेला ग्राउंड स्थित डेरा, पंवासा पारदी डेरा, चिमनगंज क्षेत्र में आकाश पेट्रोल पंप के पास का डेरा, भैरवगढ़ क्षेत्र का नाथ डेरा और घट्टिया थाना क्षेत्र का लाखेड़ा पारदी डेरा शामिल हैं। देर रात शुरू हुई कार्रवाई से डेरों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।अभियान में एएसपी शहर आलोक शर्मा, सीएसपी कोतवाली राहुल देशमुख और सीएसपी जीवाजीगंज पुष्पा प्रजापति के नेतृत्व में पांच थानों का पुलिस बल, साइबर सेल और फील्ड यूनिट की टीम शामिल रही। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को थानों में ले जाकर पूछताछ की गई और उनकी पहचान व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए कई लोग पहले से आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। साइबर सेल और फील्ड यूनिट की जांच में यह भी पता चला कि कुछ संदिग्ध उज्जैन के साथ आसपास के जिलों में भी संपत्ति संबंधी अपराधों में सक्रिय रहे हैं। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन डेटा और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शहर में संगठित अपराध, चोरी और फरार बदमाशों पर निगरानी बढ़ाने के लिए आगे भी इसी तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

साड़ी का फंदा बनाकर युवक ने लगाई फांसी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बीती शाम युवक ने घर में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिजन उसे देखने पहुंचे तो लटका देखा। युवक को उतारकर अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया है। जांच के बाद ही युवक द्वारा लगाई गई फांसी की वजह सामने आ पाएगी। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि राजेन्द्र नगर में रहने वाले भूरा पिता मदनलाल राठौर द्वारा फांसी लगाने की सूचना शासकीय चरक अस्पताल से मिली थी। देर शाम का समय होने पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। मामले में मर्ग कायम कर घटना स्थल का कमरा सील किया गया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक भूरा फव्वारा चौक क्षेत्र में दुकान पर काम करता था और शराब पीने का भी आदी था। उसने फांसी क्यों लगाई इसकी वजह परिजनों के गमगीन होने पर सामने नहीं आ पाई है। प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल मामला जांच में है।

चरक अस्पताल में बह रहा गंदा पानी, मरीजों-परिजनों का निकलना दूभर

55 लाख की ड्रेनेज योजना अधूरी, चैंबर बनते ही मिल सकेगी राहत, सड़क बंद करने की अनुमति अटकी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल चरक अस्पताल इन दिनों गंभीर ड्रेनेज समस्या से जूझ रहा है। अस्पताल परिसर में शौचालयों का गंदा पानी खुले में बह रहा है, जिससे मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को बदबू और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। हालत यह है कि कई जगह चैंबर उफन रहे हैं और अस्पताल का वातावरण अस्वच्छ बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार अस्पताल की ड्रेनेज लाइन शुरू से ही व्यवस्थित नहीं रही। अस्पताल शुरू होने के कुछ समय बाद ही चैंबर बार-बार चोक होने लगे थे। इसके बाद से शौचालयों का मलमूत्र खुले में बहने की समस्या लगातार बनी हुई है। कई बार अस्थायी सुधार किए गए, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया।समस्या के स्थायी निराकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अलग ड्रेनेज लाइन डालकर उसे मुख्य सीवरेज लाइन से जोड़ने की योजना बनाई थी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 55 लाख रुपए नगर निगम को दिए गए। निगम ने जिला अस्पताल से क्षीरसागर, बहादुरगंज होते हुए मस्तराम अखाड़ा तक अलग सीवरेज लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा कर लिया है।अधिकारियों के मुताबिक करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अब केवल मस्तराम अखाड़ा चौराहे पर चैंबर बनाकर नई लाइन को मुख्य सीवरेज लाइन से जोड़ना बाकी है। लेकिन यह काम शुरू करने के लिए सड़क को करीब 10 से 12 दिन तक बंद रखना पड़ेगा। इसी अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। इधर अस्पताल परिसर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पुलिस चौकी के सामने चैंबर उफनाने से गंदा पानी फैल रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को बदबूदार पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। नगर निगम के जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि ड्रेनेज लाइन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। मस्तराम अखाड़ा पर चैंबर बनते ही लाइन को मुख्य सीवरेज से जोड़ दिया जाएगा और चरक अस्पताल की वर्षों पुरानी गंदे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल के बदमाश ने ठगे थे एडमिशन के नाम पर 4.50 लाख

कानपुर से पूछताछ के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर उज्जैन लाई पुलिस

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 4.50 लाख की ठगी करने वाला पश्चिम बंगाल के फर्जी प्रिंसिपल कानपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर उज्जैन लाया गया है। जिससे 11 मई तक रिमांड पर पूछताछ की जायेगी।

मंछामन गणेश कालोनी में रहने वाले एमआर सतीशचंद्र पटेल एमआर ने 29 मार्च को नीलगंगा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि बेटे हर्ष का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करना था। उनके भाई महेश कुमार का पुत्र सतना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। 15 फरवरी को उसने बताया कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर वाघमारे ने बताया कि बिहार के कटिहार स्थित मेडिकल कॉलेज में सीट खाली है। प्रोफेसर का नम्बर मिलने पर उसने संपर्क किया गया। उन्होने कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आर. बी. गुप्ता का मोबाइल नम्बर दिया। चर्चा की तो पता चला कि एक छात्र की मौत होने पर सीट खाली हुई है, जो एनआरआई कोटे की है। उक्त प्रिंसिपल ने ईमेल पर कॉलेज सीट के पैकेज की जानकारी भेजी और 2 बैंक अकाउंट नम्बर के साथ वाट्सएप पर नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट पुत्र की मांगी। एक अकाउंट नम्बर कॉलेज का था। जिसमें 25 हजार रुपए जमा कराये गये, शेष राशि 4.25 लाख दूसरे खाते में जमा किये गये। 19 फरवरी को बिहार के कटिहार पहुंचने पर सामने आया कि कोई सीट खाली नहीं है और ना ही फीस जमा हुई है। कॉलेज के प्रोफेसर आरबी गुप्ता ने कॉलेज का बैंक अकाउंट देखा तो उसमें 25 हजार रुपए पटेल परिवार की ओर से भेजना सामने आये। आर. बी. गुप्ता ने कॉलेज अकाउंट में आये रुपए को लेकर कहा कि कोर्ट में मामला लगाये, रुपए लौटा दिये जायेगा। पूर्व में भी ऐसी धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। पुलिस ने सतीशचंद्र की शिकायत पर मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। एसआई यादवेन्द्र परिहार ने बताया कि बिहार कॉलेज के प्रिंसिपल गुप्ता से संपर्क करने पर पता चला कि पूर्व में भी 4 से 5 बार जयंत सरकार नामक पश्चिम बंगाल का व्यक्ति कॉलेज के नाम से ठगी कर चुका है। जयंत सरकार का पता लगाने पर सामने आया कि वह धोखाधड़ी के मामले में कानुपर पुलिस की हिरासत में है। जिससे पूछताछ के लिये प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया गया। न्यायालय के आदेश पर कानपुर से जयंत पिता ज्योति सरकार निवासी शांतिपाट भक्तिनगर जलपाई गुडी पश्चिम बंगाल को उज्जैन लाया गया है।

वह फर्जी प्रिंसिपल बनकर लोगों को अपने झांसे में लेता था। 11 मई तक पूछताछ की जायेगी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर हुई धोखाधड़ी में कुछ ओर नाम सामने आ सकते है। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जायेगें।

हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। 19 मई 2022 को तेजूबाई नामक महिला ने नरवर थाना पुलिस को अपने पति हरिराम की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और बताया था कि पति को बल्लू उर्फ बालकृष्ण महाराज अपने साथ ले गया था। उसके बाद से पति नहीं लौटा है। पुलिस ने लापता हरिराम की तलाश शुरू की, इस बीच 25 मई 2022 को एक कुएं से वृद्ध की लाश मिली। जिसकी पहचान हरिराम के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर चोंट के निशान थे। पुलिस ने मर्ग कायम जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर बल्लू महाराज उर्फ बलराम उर्फ बालकृष्ण शर्मा निवासी ग्राम आसेर थाना कायथा को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी गोकुलसिह निवासी ग्राम सारोला और महेश पांचाल निवासी ग्राम दोंता जागीर थाना मक्सी जिला देवास के साथ हत्या कर लाश ठिकाने लगाना कबूल कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 4 साल तक चली सुनवाई के बाद गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश ए.पी.एस. चैहान (विषेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट) द्वारा बल्लू उर्फ बालकृष्ण ओर गोकुल को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया पुलिस अनुसंधान के दौरान पाया गया कि आरोपी बालकृष्ण और हरिराम में लेनदेन का संव्यवहार था, आरोपी बालकृष्ण ने मृतक हरिराम को नकली सोने के हार व कान का टाप्स देकर रुपए उधार लिये थे। हरिराम द्वारा उक्त हार व कान की टाप्स बैंक में जमा करने की बात बालकृष्ण को बताई तो बालकृष्ण को लगा कि उसकी पोल खुल जायेगी तब उसने सहआरोपी गोकुल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और लालच दिया कि हार उसके हिस्से में जायेगा। हत्या में महेश पांचाल को भी शामिल किया और उसकी बाइक से हरिराम को हत्या वाली जगह तक लाया गया। जहां गोकुल और बल्लू महाराज ने हत्या कर लाश को ठिकाने लगा। प्रकरण में शासन का पक्ष पैरवीकर्ता ईश्वरसिंह केलकर विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।